आज का सुविचार

परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं, जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं ।
शिक्षा : महाभारत के पात्रों को समझो और स्वयं को देखो

भोपाल, सीहोर, दमोह, उज्जैन से एक साथ प्रकाशित

दैनिक
भोपाल टुडे

आमंत्रण मूल्य-3 रुपए | राजधानी का निष्पक्ष और निर्भीक अखबार... | पृष्ठ-8

Email: dainikbhopaltoday@gmail.com ▸▸ bhopaltoday.in ▸▸ वर्ष: 11, अंक: 313 ▸▸ भोपाल, शनिवार ,25 अप्रैल-2026 | संपादक: प्रमोद पाण्डेय | मूल्य-1 -रुपए

न्यूज ब्रीफ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रख्यात रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर किया नमन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय चेतना के प्रखर स्वर और ओजस्वी काव्यधारा के अमर रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा जैसी कृतियों के सृजन से दिनकर जी ने स्वाभिमान, संघर्ष और राष्ट्र धर्म का संदेश दिया। उनकी लेखनी से देशवासियों को सत्य और साहस के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है।

स्किन डोनेशन के लिए जन जागरण जरुरी : नेशनल बर्न्स सेंटर

मुंबई। द नेशनल बर्न्स सेंटर (एनसीबी) ने मुंबई में बताया कि देश भर में स्किन डोनेशन की भारी कमी को देखते हुए लोगों में स्किन डोनेशन के लिए जन जागरण जरुरी है। इसके लिए लोगों को आगे आना जरुरी है। नेशनल बर्न्स सेंटर के डायरेक्टर और प्लास्टिक सर्जन डॉ. सुनील केसवानी ने आज पत्रकारों को बताया कि स्किन डोनेशन और मरीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भारी अंतर है। मुंबई में स्किन बैंकों को हर साल आवश्यकता के उलट महज़ 25 फीसदी स्किन डोनेशन ही हासिल हो पाती है। आम तौर पर 10 में से 1 व्यक्ति को ही स्किन डोनेशन अथवा स्किन डोनेशन की उचित प्रक्रिया की जानकारी होती है। जागरुकता की इसी कमी के चलते हर साल आग से झुलस जाने वाले मरीज़ों में से न्यूनतम मरीज़ों को ही स्किन ट्रांसप्लांट का लाभ हासिल हो पाता है। यह एक बेहद गंभीर मसला है। डॉ. केसवानी ने कहा कि हम हर साल लगभग 300 जागरुकता अभियानों का आयोजन करते आ रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में लोग स्किन डोनेट करने के लिए प्रेरित हो सकें। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जागरुकता से जुड़े हमारे इन प्रयासों के चलते स्किन डोनेशन से संबंधी इस कमी को पूरा किया जा सकेगा और इसके बारे में लोगों की समझ में भी ख़ासा इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि आग में झुलस जाने वाले लगभग 70 फीसदी मरीज़ों की उम्र 15 से 35 साल के बीच होती है। स्किन ट्रांसप्लांटेशन के अभाव के चलते मरीज़ों व उनके परिजनों पर परिणाम देखने को मिलते हैं। उचित समय पर की जाने वाले स्किन ग्राफ्टिंग और सही चिकित्सा के चलते आग में झुलस जाने वाले मरीज़ों को कई तरह की जटिलताओं से बचाया जा सकता है और उचित तरीके से उनका पुनर्वास भी संभव होता है। स्किन डोनेशन का फ़ैसला किसी शख़्स की मौत के 6 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। स्किन डोनेट करने के लिए दाता का स्थानीय स्किन बैंक के तहत पंजीकृत होना भी आवश्यक होता है।

पंचकूला में कांग्रेस उम्मीदवार ने किया नामांकन, हुड्डा गुट ने बनाई दूरी

चंडीगढ़। हरियाणा के पंचकूला नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से सामने आ गई। शुक्रवार को नगर निगम चुनाव के दौरान मेयर पद की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज के नामांकन कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के सभी नेता गायब रहे। अंबाला के सांसद वरूण चौधरी के हवाले से पहले ही समाचार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था कि वह नामांकन में शामिल नहीं होंगे। पंचकूला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मेयर पद उम्मीदवार श्रीमती सुधा भारद्वाज सहित समस्त 20 वार्ड प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की उपस्थिति में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। गाडियों का काफिला लेकर सुधा भारद्वाज नामांकन स्थल पर पहुंची। जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा तथा रणदीप सिंह सुरजेवाला एवं स्थानीय विधायक चंद्रमोहन ने इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार को भारी बहुमत से जीतने की अपील की। चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरमोहिन्दर सिंह लक्की, राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध, विधायक अकरम खान,पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, शमशेर सिंह गोगी, जसबीर मलौर, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पर्ल चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे लेकिन हुड्डा गुट के नेताओं की गैरहाजिरी आज चर्चा का विषय रही।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र कहा- आर्थिक चुनौतियों का समाधान हो

भोपाल टुडे,कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि 152 सीटों में से बीजेपी 110 से ज्यादा सीटें जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बताया कि बीजेपी की बंगाल टीम ने अपना आकलन किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण को भी ध्यान में रखते हुए बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में रिकॉर्ड मतदान को लेकर शाह ने कहा कि गुरुवार को बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। उन्होंने कहा कि मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है, वह पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं प्रथम चरण में वोट डालने वाले बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भय से भरोसे की यात्रा को बहुत अच्छे से शुरू किया है और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे

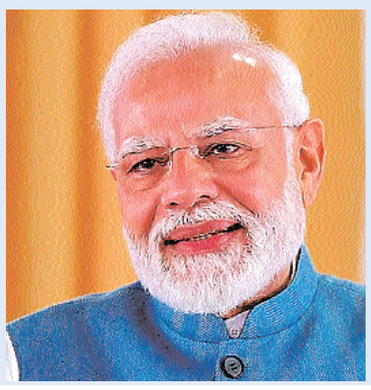

बढ़ाएंगे। बंगाल की जनता के नाम संदेश में साह ने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा से जुड़ चुका है। आपका प्यार, आपका उत्साह और आपका भरोसा, पूरे प्रचार अभियान में मोदीजी के लिए सामने से दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि ये भरोसा वोट में परिवर्तित होकर बीजेपी की विजय कराएगा। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में सीएम यह कहती हैं कि महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, वहां उन्हें सत्ता में नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद, रात के 1 बजे भी एक युवा लड़की बेझिझक अपना स्कूटर चला पाएगी और किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होगी कि वह उस पर बुरी नजर डाल सके। उन्होंने कहा कि एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर, आरजी कर कॉलेज की पीड़ित की मां और संदेशखाली की पीड़ित को उम्मीदवार बनाया गया है, जिन लोगों ने टीएमसी-समर्थित गुंडों की हिंसा का सामना किया है, वे अब विधानसभा में बैठेंगे और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने में मदद करेंगे। आने वाले दिनों में बंगाल इसी तरह का बदलाव देखेगा।

डेयरी गतिविधियों में 26 हजार गांवों को जोड़ने और प्रतिदिन 52 लाख कि.ग्रा. दुग्ध संकलन का लक्ष्य

प्रदेश में सहकार से हो रहा है डेयरी गतिविधियों का विस्तार: मुख्यमंत्री

दुग्ध क्षेत्र में पारदर्शिता और ब्रांड सुदृढ़ीकरण पर होगा विशेष फोकस

दुग्ध समितियों में महिला सदस्यता को किया जाए प्रोत्साहित

मोबाइल ऐप से होगा दुग्ध संकलन

जिला स्तर पर कार्यक्रमों में होगा आदर्श पशुपालकों का सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक

भोपाल टुडे, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी रूप से सहायक है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार डेयरी गतिविधियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के दुग्ध संघों को दिए जा रहे सहयोग से दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है और किसानों को भी दूध के बेहतर दाम मिल रहे हैं। सहकार के भाव से डेयरी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। दुग्ध समितियों में महिला सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेयरी सहकारी कवरेज के विस्तार और सुदृढ़ीकरण, नई डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और पशु चारा संयंत्र के आधुनिकीकरण, डेयरी वैल्यू चैन के डिजीटलाइजेशन, पारदर्शिता और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। डेयरी विकास योजना के अंतर्गत 26 हजार गांवो को

जोड़ने, प्रतिदिन दुग्ध संकलन 52 लाख किलोग्राम तक करने का लक्ष्य रख, गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये निर्देश मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक में दिए।

मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में हुई बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल, वरिष्ठ विधायक तथा वरिष्ठ विधायक एवं अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अध्यक्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मीनेष शाह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध क्षेत्र में अनुभव का लाभ राजधानी से लेकर ग्राम स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। दूध और दुग्ध उत्पादों के बिक्री में सुधार के लिए ब्राण्ड सुदृढ़ीकरण और नई पैकेजिंग डिजाइन कर उत्पादों की पहुंच का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुग्ध उत्पादन में वद्धि और विभिन्न दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए किसानों को नवाचार करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों तथा प्रदेश के युवाओं को डेयरी टेक्नोलॉजी की नई तकनीकों से परिचित कराने की भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदर्श पशुपालकों को सम्मानित करने, दूधारू पशुओं की प्रदर्शनी आयोजित करने और डेयरी के संबंध में सूचना सम्प्रेषण के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यअनुबंध करने के बाद वर्ष 2025-26 में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया तथा 701 निष्क्रिय दुग्ध समितियों को क्रियाशील किया गया। प्रदेश में प्रतिदिन 9 लाख 67 हजार कि.ग्रा. दुग्ध संकलन किया जा रहा है, साथ ही 153 नवीन बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई है। दूध और दूध उत्पादों का क्रेडिट पर विक्रय बन्द कर दिया गया है। प्रदेश में दुग्ध संकलन मोबाइल ऐप से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दुग्ध प्रदायकों को दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सकेगी।

पीएम मोदी 28 को मप्र को देंगे 2 नई अमृत भारत की सौगात

भोपाल-इटारसी-जबलपुर-हरदा-खंडवा के लोगों को मिलेगा विशेष लाभ

भोपाल टुडे, भोपाल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश की अत्याधुनिक और किफायती अमृत भारत एक्सप्रेस की दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से एक ट्रेन बनारस से और दूसरी अयोध्या कैंट से संचालित होगी, जो मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और धार्मिक शहरों को सीधे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से जोड़ेंगी।

अयोध्या-लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच पहला रूट: पहला रूट अयोध्या कैंट से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच है, जो जबलपुर और इटारसी होकर गुजरेगा। यात्रा के दौरान प्रयागराज से चलकर यह ट्रेन मानिकपुर, सतना, जबलपुर और इटारसी जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद भुसावल, जलगांव और नासिक होते हुए मुंबई तक जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से जबलपुर और सतना के यात्रियों को अयोध्या और मुंबई के लिए एक तेज विकल्प मिलेगा।

भोपाल-इटारसी को मिलेगी सीधा कनेक्टिविटी: दूसरा रूट बनारस से हडपसर (पुणे) के बीच है। बनारस से शुरू होने वाली यह अमृत भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इटारसी को सीधा कनेक्टिविटी देगी। बनारस और प्रयागराज के रास्ते यह ट्रेन बीना, रानी कमलापति (भोपाल), नर्मदापुरम और इटारसी पहुंचेगी। इसके बाद यह हरदा, खंडवा और भुसावल होते हुए पुणे के हडपसर स्टेशन तक जाएगी। यह ट्रेन खासतौर पर भोपाल और नर्मदापुरम के उन यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी जो पुणे या बनारस की यात्रा करते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से गैर-वातानुकूलित ट्रेन है, लेकिन इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए फोल्डेबल स्नैक टेबल, मोबाइल होल्डर, चार्जिंग पॉइंट और आधुनिक शौचालयों के साथ बेहतर कुशन वाली सीटें दी गई हैं।

बंगाल में बन रही बीजेपी की सरकार, पहले चरण में 110 सीटें जीतेगी: शाह

भोपाल टुडे, कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि 152 सीटों में से बीजेपी 110 से ज्यादा सीटें जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बताया कि बीजेपी की बंगाल टीम ने अपना आकलन किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण को भी ध्यान में रखते हुए बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में रिकॉर्ड मतदान को लेकर शाह ने कहा कि गुरुवार को बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सभी

रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। उन्होंने कहा कि मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है, वह पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं प्रथम चरण में वोट डालने वाले बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भय से भरोसे की यात्रा को बहुत अच्छे से शुरू किया है और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बंगाल की जनता के नाम संदेश में साह ने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा से जुड़ चुका है। आपका प्यार, आपका उत्साह और आपका भरोसा, पूरे प्रचार अभियान में मोदीजी के लिए सामने से दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि ये भरोसा वोट में परिवर्तित होकर बीजेपी की विजय कराएगा। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में सीएम यह कहती हैं कि महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, वहां उन्हें सत्ता में नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद, रात के 1 बजे भी एक युवा लड़की बेझिझक अपना स्कूटर चला पाएगी और किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होगी कि वह उस पर बुरी नजर डाल सके। उन्होंने कहा कि एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर, आरजी कर कॉलेज की पीड़ित की मां और संदेशखाली की पीड़ित को उम्मीदवार बनाया गया है, जिन लोगों ने टीएमसी-समर्थित गुंडों की हिंसा का सामना किया है, वे अब विधानसभा में बैठेंगे और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने में मदद करेंगे।

बंपर वोटिंग पर केजरीवाल का तंज, मोदी जी की एसआईआर प्रक्रिया उन्हीं के खिलाफ

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में रिकॉर्ड मतदान के बाद मोदी जी की एसआईआर प्रक्रिया उन्हीं के खिलाफ जा रही है। केजरीवाल ने पोस्ट कर लिखा कि बंगाल में यह बात सामने आ रही है कि लोग एसआईआर के खिलाफ मजबूती से वोट डाल रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा यह घोषणा करने के कुछ ही समय बाद आई कि पश्चिम बंगाल

और तमिलनाडु में स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है, क्योंकि मतदान शाम 6 बजे समाप्त हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से बंगाल और तमिलनाडु में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बंगाल में प्रथम चरण में तमिलनाडु के 84.80 प्रतिशत की तुलना में 91.91 प्रतिशत का उल्लेखनीय रूप से उच्च मतदान दर्ज किया गया। उच्च मतदान सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को दिखाता है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जिसमें दक्षिण दिनाजपुर में सबसे अधिक 94.85 प्रतिशत, उसके बाद कूच बिहार में 94.54 प्रतिशत, बीरभूम में 93.70 प्रतिशत, जलपाईगुड़ी में 93.23 प्रतिशत और मुर्शिदाबाद में 92.93 प्रतिशत मतदान हुआ।

नीतीश कुमार 20 सालों में बिहार को किया दिग्भ्रमित

सीएम सम्राट 20 दिन में ही दिग्भ्रमित करने लगे: राजेश राठौड़

पटना।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पटना सहित 11 सेटेलाइट शहरों के निर्माण की बात पर बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि नीतीश कुमार 20 सालों में बिहार को दिग्भ्रमित किया तो वहीं सम्राट चौधरी 20 दिन में ही राज्य को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में बिहार के निवासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 दिन भी पदभार ग्रहण किए हुए नहीं हुआ और बिहारियों को झूठे सपने बेचकर ठगने का प्रयास करने लगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले अधिकारियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वें वर्तमान मुख्यमंत्री को बरगला रहे हैं और उन्हें झूठे सपने दिखा रहे हैं जैसे नीतीश सरकार में उन्होंने राज्य को धोखे में रखा। बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि बिहार पहले से कर्ज में डूबा है

और 12 हजार करोड़ का नया कर्ज मांगा है। राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रहा है, छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि नहीं मिल पा रही है और ट्रेज़री में पैसे की निकासी पर रोक है। ऐसे में 11 सेटेलाइट शहरों के निर्माण में प्रत्येक शहरों में नए सेटेलाइट टाउन बनाने के लिए कितनी राशि आवंटित हो रही है और पैसे कहां से लाएं जा रहे हैं इसकी भी स्पष्ट जानकारी राज्य की जनता को देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य की राजधानी पटना में यदि बिल्डर्स ध्यान न दें तो अपार्टमेंट तक पहुंच पथ और शहर की गली का विकास भी यह सरकार कराने में असक्षम है।

जीएसटी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 162 अधिकारियों का तबादला

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सर्जरी का बड़ा उदाहरण सामने आया है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर ट्रेड एंड टैक्सेस (जीएसटी) विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों को अचानक स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई 8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री के विभागीय दौरे के बाद सामने आई अनियमितताओं के आधार पर की गई है। दौरे के दौरान कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद तत्काल सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें तीन असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल हैं। ये अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात थे।

जिससे प्रशासनिक निष्पक्षता और कार्यकुशलता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। सरकार का मानना है कि लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनाती से व्यवस्था में ढीलापन और अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है।

एंकर | स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती

मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी की शीघ्र होगी पूर्ति: उप मुख्यमंत्री देवड़ा

भोपाल टुडे, भोपाल।

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने शुक्रवार को मंदसौर जिले के स्वास्थ्य एवं अधोसंरचना विकास को नई गति देते हुए इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय, मंदसौर में कुल 29 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।

उपमुख्यमंत्री देवड़ा ने 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित 100 बिस्तरीय नवनिर्मित वार्ड तथा 17 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बने 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) भवन का लोकार्पण किया। साथ ही 4 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से चांदाखेड़ी फंटा से खजुरिया मार्ग

निर्माण कार्य का भूमि-पूजन भी किया।

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी को धीरे-धीरे दूर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन संस्थानों से प्रशिक्षित होकर निकलने वाले विद्यार्थी प्रदेश में ही सेवाएं देंगे, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि जिला चिकित्सालय मंदसौर में आज जो सुविधाएं जोड़ी गई हैं, वे क्षेत्र के नागरिकों के लिए बड़ी सौगात हैं और इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य भवन केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह भविष्य की आशाओं का केंद्र है। यह विशेष रूप से माताओं और बहनों की सेवा के लिए समर्पित रहेगा तथा समाज के लिए प्रेरणादायक केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य केवल भौतिक अधोसंरचना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर किया जा रहा है। बदलते हुए भारत में परिवर्तन को महसूस किया जा रहा है। सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। विकास को नए पंख लगे हैं। विकास की धारा बह रही हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि सरकार निरंतर विकास कार्यों को गति दे रही है और विभिन्न क्षेत्रों में नई सौगातें प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर बजट आवंटन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप सुविधाओं में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है। सांसद बंशीलाल गुर्जर ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने एक नई कार्य संस्कृति विकसित की है, जिसमें गुणवत्ता के साथ कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

कार्यक्रम के अंत में 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत मरीजों को फूड बास्केट वितरित किए गए।

न्यूज ब्रीफ

निगम द्वारा जल परीक्षण, लीकेज सुधार एवं शिकायतों के निराकरण हेतु कार्यवाही निरंतर जारी

भोपाल। नगर निगम, भोपाल द्वारा शहर के नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु पानी की गुणवत्ता की जांच, लीकेज सुधार एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में निगम अमले ने गुरूवार को विभिन्न झुग्गी बस्तियों सहित संपूर्ण शहर से जल के परीक्षण हेतु कुल 99 स्थानों से जल के नमूने लिये गये। निगम द्वारा 08 परीक्षण शालाओं के माध्यम से जल का परीक्षण किया जा रहा है। निगम अमले ने 49 स्थानों पर पाईप लाईनों के लीकेज सुधारे और सी.एम.हेल्पलाईन एवं महापौर हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में से 05 शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण ढंग से निराकरण किया गया। महापौर श्रीमती मालती राय के निर्देश एवं निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के आदेश पर नगर निगम, भोपाल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दलों ने शहर की झुग्गी बस्तियों सहित संपूर्ण शहर में कुल 99 जल के नमूने लेकर गंध, रंग, स्वाद, रेसिडुअल क्लोरीन, पीएच, टरबीडिटी व बैक्टेरिया की जांच 08 परीक्षण शालाओं के माध्यम से कराई जा रही है। निगम अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 49 स्थानों पर पाईप लाईनों के लीकेज भी सुधारे और सी.एम.हेल्प लाईन, महापौर हेल्प लाईन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों में से 05 शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्ण ढंग से किया। निगम अमले ने अभी तक झुग्गी बस्ती क्षेत्रों के 8124 स्थानों सहित शहर में कुल 17582 जल के नमूने लेकर 08 परीक्षण शालाओं के माध्यम से जल की गुणवत्ता की जांच कराई साथ ही 4433 लीकेज सुधारे। निगम अमले ने वर्तमान तक 12737 सीवेज चेम्बरों की सफाई कराई।

सड़कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले 20 पशुओं को निगम अमले ने कांजी हाउस भेजा

भोपाल। नगर निगम द्वारा सड़कों, फुटपाथों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को पकड़कर कांजी हाउसों में भेजने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के गौवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने गुरूवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र विचरण करने वाले 20 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउसों में भेजा जबकि हाका पार्टी द्वारा 18 पशुओं को सड़कों से हटाया और 02 बीमार/घायल पशुओं को पशु चिकित्सालय आसरा में भेजा। निगम अमले ने 18 पशुओं को महामृत्युंजय गौशाला भेजने की कार्यवाही की।

निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर निगम की गोवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने शहर के अशोका गार्डन, 80 फिट रोड, पुष्पा नगर, पंजाबी बाग, लालघाटी, बैरागढ़, भैंसाखेडी, ईदगाह हिल्स आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे 20 पषुओं को पकड़कर कांजी हाउसों में भेजा जबकि हाका पार्टी द्वारा 18 पशुओं को सड़कों से हटाया और 02 बीमार/घायल पशुओं को पशु चिकित्सालय आसरा में भेजा। निगम अमले ने खजूरीकलां कांजी हाउस से 18 पशुओं को महामृत्युंजय गौशाला भेजने की कार्यवाही भी की।

गोलीकांड और गोकशी का फरार इनाम बदमाश लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार

भोपाल। ऐशबाग पुलिस ने ईंटखेड़ी थाना इलाके में हुए गोलीकांड और ऐशबाग क्षेत्र में गोकशी के मामले में फरार चल रहे 5 हजार के इनामी बदमाश को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थाना पुलिस के अनुसार कम्मू का बाग में रहने वाला गुराज उर्फ शारिक खान पिता जाहिद खान (32) थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है। उसके खिलाफ ईंटखेड़ी में गोली चलाने के मामले सहित शहर के अलग-अलग थानो में दर्जन भर से अधिक अपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा गोकशी के मामले में वह करीब सालभर से फरार चल रहा था। बीते दिन टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि वह किसी वारदात को अंजाम देने की नियत से जानलेवा हथियार लेकर सोनिया गांधी कॉलोनी में घूम रहा है। खबर मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस मिला। थाना पुलिस के अनुसार 18 अगस्त, 2025 को दर्ज गोकशी के मामले में आरोपी रुसी खॉन और जब्बार को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। वहीं गुराज और अमन फरार चल रहे थे। उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित था। कम्मू का बाग में रहने वाले गुराज उर्फ शारिक खान के घर पर रिमशा और उसके बदमाश पति दानिश अली ने एक महीना पहले गोली चलाकर सनसनी फैला दी थी।

आपात स्थिति में त्वरित सीपीआर प्रदान कर प्रतिबद्धता को साकार किया

मतदान ड्यूटी के दौरान मध्यप्रदेश पुलिस के पुलिसकर्मियों द्वारा पीठासीन अधिकारी का जीवन सुरक्षित किया गया

भोपाल टुडे, भोपाल।

मध्यप्रदेश पुलिस के पुलिसकर्मियों द्वारा निर्वाचन ड्यूटी के दौरान प्रदर्शित मानवीय संवेदनशीलता, तत्परता एवं कर्तव्यनिष्ठा का एक प्रेरणादायी उदाहरण पश्चिम बंगाल राज्य के जिला पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर स्थित प्रणबानंद विद्यानगर, मतदान केंद्र क्रमांक–57 पर सामने आया, जहां एक आपात स्थिति में समयबद्ध एवं प्रशिक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से पीठासीन अधिकारी का जीवन सुरक्षित किया गया।

इसी दौरान विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया के बीच पीठासीन अधिकारी अरूप सान्याल को अचानक हृदयाघात (हार्ट अटैक) आ गया, जिससे वे अचेत हो गए और मतदान केंद्र पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई। ऐसे संवेदनशील समय में वहां तैनात मध्यप्रदेश पुलिस की द्वितीय बटालियन, विशेष सशस्त्र बल , ग्वालियर के पुलिसकर्मियों ने अत्यंत तत्परता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया।

सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) वासुदेव सिंह, आरक्षक क्रमांक 75 दीपक यादव, आरक्षक क्रमांक 112 ब्रजेश कुमार एवं आरक्षक क्रमांक 976 संदीप कुमार ने बिना विलंब किए पीड़ित अधिकारी को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए सीपीआर प्रारंभ किया। प्रशिक्षित एवं समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी की स्थिति में शीघ्र सुधार हुआ तथा उनकी नाड़ी एवं श्वसन क्रियाएं पुनः संचालित होने लगीं।

उक्त पुलिसकर्मियों द्वारा समानांतर रूप से चिकित्सा सहायता भी तत्काल सुनिश्चित कराई गई, जिससे पीड़ित अधिकारी को शीघ्र ही चिकित्सालय पहुंचाकर आगे का उपचार उपलब्ध कराया जा सका। इस त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक संभावित गंभीर स्थिति को नियंत्रित करते हुए एक बहुमूल्य जीवन की रक्षा संभव हो सकी।

यह घटना मध्यप्रदेश पुलिस के मूल मंत्र वादा वर्दी का की भावना को वास्तविक रूप में अभिव्यक्त करती है, जिसमें हर परिस्थिति में नागरिकों की सुरक्षा एवं जीवन रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। कानून-व्यवस्था के दायित्वों के साथ-साथ मानवीय मूल्यों के प्रति यह प्रतिबद्धता पुलिस बल की संवेदनशीलता एवं सेवा भावना को सशक्त रूप से परिलक्षित करती है।

उक्त पुलिसकर्मियों के इस साहसिक, सराहनीय एवं प्रेरणादायी कार्य के लिए उन्हें विधिवत प्रशस्ति एवं पुरस्कार प्रदान कर पुलिस महानिरीक्षक अरविन्द सक्सेना द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, सेवा एवं सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सतत सुदृढ़ करते हुए हर परिस्थिति में संवेदनशील, सजग एवं उत्तरदायी भूमिका निभाती रहेगी–इसी भावना में वादा वर्दी का निहित है।

अगले चार साल में हवाई यात्रियों की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी

इंदौर, देवास और उज्जैन अब एयरपोर्ट सिटी के रूप में होंगे विकसित, 11 हवाई पट्टियों पर मिलेगा प्रशिक्षण

भोपाल टुडे, भोपाल।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उड़ान विजन को साकार करते हुए मध्यप्रदेश को उत्कृष्ट विमानन केन्द्र और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां 2030 तक हवाई यात्री क्षमता 5.5 मिलियन से बढ़कर 10 मिलियन सालाना तथा माल कार्गो क्षमता 20 हजार मैट्रिक टन करने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक इंदौर, देवास, उज्जैन क्षेत्र को एयरपोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

प्रदेश में विमानन क्षेत्र को विकेंद्रीकृत करते हुए हवाई सुविधाओं को तहसील स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हवाई सेवाएं केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि हर क्षेत्र तक पहुंचें। इसी दृष्टि से प्रत्येक तहसील ब्लॉक में हेलीपैड विकसित करने की योजना है। प्रदेश में हर 150 किलोमीटर पर एक कॉमर्शियल एयरपोर्ट, 75 किलोमीटर पर एयरस्ट्रिप और 45 किलोमीटर के दायरे में हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करेगी और दूरस्थ क्षेत्रों के आर्थिक विकास को नई गति देगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, मध्यप्रदेश आस्था, अध्यात्म और अनुपम शिल्पकला का संगम है। उज्जैन के श्री महाकाल लोक, ओंकारेश्वर के एकात्म धाम, खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहर और ओरछा-चित्रकूट की आस्थाएँ जन-मानस में रची-बसी हैं। इन स्थलों तक सहज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा' और 'धार्मिक पर्यटन हेली सेवा' प्रभावी माध्यम बन रही हैं। वर्तमान में यह सेवा प्रदेश के 8 प्रमुख केंद्रों-भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को आपस में जोडक़र श्रद्धा और पर्यटन को नए पंख लगा रही है। हाल ही में ओरछा और चित्रकूट जैसे पावन धामों के लिए प्रारंभ हुई हेली सेवा ने श्रद्धालुओं के लिए 'हरि-हर-दर्शन कीको और भी सरल, सुखद और स्मरणीय बना दिया है। विगत दो वर्षों में मध्यप्रदेश ने हवाई सेवाओं के विस्तार में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। दतिया प्रदेश के 8वें हवाई अड्डे के रूप में अपनी सेवा दे रहा है। रीवा, सतना और दतिया की सफलता के बाद अब शिवपुरी और उज्जैन में भी नए हवाई अड्डों की तैयारी तेजी से चल रही है। रीवा हवाई अड्डा पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए विकास का नया इंजन बन चुका है।

परमाली वालेस में तिलक-बिंदी प्रतिबंध का विरोध

हिंदू उत्सव समिति ने किया प्रदर्शन, कर्मचारियों को बांधा कलावा

भोपाल टुडे,भोपाल।

लेंसकार्ट कंपनी जैसी घटना के बाद मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में परमाली वालेस कंपनी में कर्मचारियों के धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध को लेकर विवाद गहरा गया है। शहर के एमपी नगर स्थित परमाली वालेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ हिंदू उत्सव समिति ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। समिति के अध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने नोटिस जारी कर कर्मचारियों को तिलक, अंगूठी, कड़ा, बाली, मंगलसूत्र और बिंदी जैसे धार्मिक प्रतीक पहनकर आने से मना किया है। उन्होंने इसे धार्मिक आस्था और परंपराओं पर आघात बताते हुए कहा कि इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हिंदू उत्सव समिति ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही कंपनी के उत्पादों के बहिष्कार की अपील भी की गई है। शुक्रवार को समिति के कार्यकर्ता बीडीए कार्यालय पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन के बाद फैक्ट्री पहुंचे। वहां उन्होंने कर्मचारियों के समर्थन में तिलक लगाया और कलावा बांधा। फिलहाल, मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं और प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। एक कर्मचारी ने दावा किया कि जब वह कलावा और तिलक लगाकर फैक्ट्री पहुंचा, तो उसे बाहर कर दिया गया। इससे कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल है। फैक्ट्री के मैनेजर वीएस राजपूत ने बताया कि यह सर्कुलर कंपनी की ओर से जारी किया गया था। उनका कहना है कि इन वस्तुओं के उपयोग से प्रोडक्ट रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि समिति की मांग पर विचार किया जाएगा और नोटिस वापस लेने की कोशिश की जाएगी। परमाली वालेस प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में शासित है। यह कंपनी लकड़ी और रेशे आधारित सांचों के निर्माण में लगी हुई है। परमली वालेस प्राइवेट लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी है, जिसकी स्थापना 17 अगस्त, 1961 को हुई थी। इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह मध्यप्रदेश में स्थित है।

जब रक्षक ही मौन हो जाएं, तब अन्याय की आवाज बुलंद होती है

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मप्र पुलिस को लिखा खुला पत्र

भोपाल टुडे,भोपाल।

मध्यप्रदेश में हाल ही में बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी द्वारा एक आईपीएस अधिकारी को धमकी देने की घटना को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पुलिस की भूमिका और कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया है। मामले को लेकर उन्होंने एमपी पुलिस को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा- घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल एक व्यक्ति की भाषा या व्यवहार का मामला नहीं है, बल्कि यह उस खतरनाक माहौल का संकेत है जिसमें सत्ता का अहंकार कानून और संविधान पर हावी होता जा रहा है।

उन्होंने लिखा है कि मैं यह पत्र केवल एक घटना के संदर्भ में नहीं, बल्कि उस व्यापक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिख रहा हूं, जिसमें बार-बार ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जहां भाजपा नेता खुलेआम पुलिस अधिकारियों को डराने, दबाव बनाने या अपमानित करने का प्रयास करते हैं। उससे भी ज्यादा चिंताजनक यह है कि इन घटनाओं के बाद पुलिस तंत्र की प्रतिक्रिया अक्सर बेहद सीमित, संयमित और कभी-कभी मौन ही रह जाती है।

तब आपकी आवाज धीमी क्यों पड़ जाती: उन्होंने लिखा कि मेरा पुलिस अधिकारियों से एक सीधा सवाल है कि आखिर वह कौन-सी परिस्थितियां हैं, जिन्होंने देश के सबसे प्रशिक्षित, अनुशासित और साहसी अधिकारियों को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है? जब अन्याय के खिलाफ दहाडने की जरूरत होती है, तब आपकी आवाज धीमी क्यों पड़ जाती है? और जब आम नागरिक सामने होता है, तब वही तंत्र इतना कठोर और आक्रामक कैसे हो जाता है? क्या यह सच नहीं है कि जब पुलिस निष्पक्ष और संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, तब किसी भी नेता या प्रभावशाली व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वह उसे आंख दिखा सके? लेकिन जब वही पुलिस बीजेपी सरकार के अनैतिक कार्यों की संरक्षक बनती हुई दिखाई देती है, तब उसे दबाव भी झेलना पड़ता है और अपमान भी सहना पड़ता है।

पत्र में आक्रोश कम और विवशता ज्यादा: मैंने आईपीएस एसोसिएशन का पत्र भी पढ़ा। उस पत्र में आक्रोश कम और विवशता ज्यादा नजर आती है। यह एक मजबूत और स्वाभिमानी संस्था की आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसे तंत्र की अपील प्रतीत होती है जो भीतर से दबाव में है। यह स्थिति केवल पुलिस के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि यदि कानून लागू करने वाली संस्था ही असहाय दिखेगी, तो आम नागरिक का विश्वास किस पर टिकेगा?

2011 से 17 आदेश हवा में... अब जनसंख्या गणना में झोंकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं की सेवाएं हो रहीं प्रभावित

भोपाल टुडे,भोपाल।

प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 से अब तक करीब 17 बार आदेश जारी किए जा चुके हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आईसीडीएस के मूल कार्यों के अलावा अन्य विभागीय काम न लिए जाएं, लेकिन जिलास्तर पर इन आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। चुनाव ड्यूटी के बाद अब फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जनसंख्या गणना और सर्वे कार्यों में झोंकने की तैयारी और नियुक्ति को लेकर मिल रहे मैसेज से महिलाओं की नाराजगी भडक़ा दी है।

दूधमुंहे बच्चों को गोद में लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या की ड्यूटी करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि एसआईआर के दौरान कई गर्भवती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिन-रात नौकरी की थी, लेकिन अब उनके हाथ में नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं। उन्हें छोडक़र जनसंख्या की गिनती नहीं कर सकते। चुनाव की प्रक्रिया के भुगतान को लेकर भी महिलाओं ने कहा कि उसका भुगतान अब तक नहीं मिला। मासिक

मानदेय भी समय पर नहीं मिल रहा। ऐसे में सिर्फ 25 हजार का लालच दिखाकर सरकार 2 साल तक काम करवाना चाहती है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर कार्य में लगाया गया, मगर आज तक एक रुपया नहीं मिला। अब फिर जनसंख्या गिनने का काम थोपने की तैयारी की जा रही है, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले ही उनसे महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, सर्वे, चुनाव, शिक्षा और अन्य विभागों के काम लिए जा रहे हैं।

बिना नंबर की बाइक से आये नकाबपोश बदमाशो ने गोली चलाकर फैलाई दहशत

भोपाल टुडे,भोपाल।

शहर के श्यामलाहिल्स थाना इलाके में बुधवार देर रात बिना नंबर की बाइक से आये अज्ञात नकाबपेश बदमाशो ने एक युवक के घर के बाहर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गये। बताया गया है कि बदमाशो ने पहले युवक के घर जाकर उसका नाम लेकर चिल्लाचोट की और कुछ देर बाद दो राउंड हवाई फायरिंग कर भाग गये। जिस युवक का नाम लेकर फायरिंग की गई थी। उसका एक बदमाश से कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, वारदात से कुछ देर पहले ही वह बदमाश और युवक श्यामलाहिल्स थाने से समझौता करके निकले थे। पीड़ित युवक ने उसी बदमाश पर फायरिंग करने या अपने किसी गुर्गे से करवाने का संदेह जताया है। पुलिस को मौके से चली हुई गोली एक खोल बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आगे की जॉच शुरु कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्यामलाहिल्स थाना क्षेत्र में रहने वाला राजकुमार राजपूत प्राईवेट नौकरी करता है। राजकुमार की मां शारदा बाई राजपूत पति स्वर्गीय दयाराम राजपूत (55) किलोल पार्क के पास पेट्रोल पंप की पीछे की बस्ती में रहती है, हालांकि लगभग चार साल से राजकुमार अपनी मॉ से अलग रह रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले आकाश बाथम से किसी बात को लेकर राजकुमार का कुछ दिनो पहले विवाद हो गया था। इसके बाद आकाश और उसके साथी राजकुमार को तलाशते हुए उसकी मां के घर भी जा रहे थे। इसकी शिकायत शारदा बाई ने श्यामलाहिल्स थाने में की जिसके बाद थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने तलब किया। बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे तक आकाश और राजकुमार थाने में ही मौजूद रहे और एक दूसरे से समझौता किया। थाने से निकलकर राजकुमार अपने घर पहुंचा, कुद देर बाद ही उसके घर के बाहर बाईक सवार बदमाश आये और उसका नाम लेकर हवाई फायर कर दिए।

भोपाल, जबलपुर-उज्जैन समेत 11 जिलों में लू का अलर्ट

राजस्थान की गर्म हवा ने मप्र में बढ़ाई तपिश

भोपाल टुडे, भोपाल।

राजस्थान से आ रही गर्म हवा से मध्य प्रदेश में तपिश बढ़ गई है। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम और सागर संभाग के शहरों में हीट वेव यानी लू जैसे हाल हैं। शनिवार को भी 11 जिलों में लू का अलर्ट है। नर्मदापुरम में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, जिन शहरों में लू चलने का अलर्ट है, उनमें निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर शामिल हैं।

भोपाल समेत कई शहरों में रात में तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास ही चल रहा है। नर्मदापुरम में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक है। यहां आने वाले दिनों में वॉर्म नाइट की स्थिति भी बन सकती है। वॉर्म नाइट मौसम की एक ऐसी स्थिति है, जब रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा होता है। यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री तक अधिक हो। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक रहा हो। यदि रात का तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री से अधिक बढ़ जाए, तो इसे सीवियर वॉर्म नाइट कहा जाता है। प्रदेश में फिलहाल सीवियर वॉर्म नाइट की स्थिति नहीं है।

अप्रैल के आखिरी में बारिश के आसार

मौसम विभाग की मानें तो अप्रैल के आखिरी में बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) की वजह से ऐसा होगा। उधर, गर्मी का असर बढ़ते ही मौसम विभाग ने बचाव की एडवायजरी भी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वे दिनभर पर्याप्त पानी पीएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में न रहें। हल्के वजन और रंग के सूती कपड़े पहनें। बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर ध्यान रखें।

न्यूज ब्रीफ

सड़कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले 17 पशुओं को निगम अमले ने कांजी हाउस भेजा

भोपाल। नगर निगम द्वारा सड़कों, फुटपाथों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को पकड़कर कांजी हाउसों में भेजने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के गौवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र विचरण करने वाले 17 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउद्यसों में भेजा जबकि हाका पार्टी द्वारा 20 पशुओं को सड़कों से हटाया और 01 बीमार/घायल पशु को पशु चिकित्सालय आसरा में भेजा। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर निगम की गोवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने शहर के रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं. 01, 80 फिट रोड, पुष्पा नगर, अशोका गार्डन, मीनाल रेसीडेंसी, अयोध्या बायपास, भोपाल मेमोरियल अस्पताल, करोद मंडी, आनंद नगर, रायसेन रोड पटेल नगर, कोकता, खजूरी, साकेत नगर आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे 17 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउसों में भेजा जबकि हाका पार्टी द्वारा 20 पशुओं को सड़कों से हटाया और 01 बीमार/घायल पशु को पशु चिकित्सालय आसरा में भेजा।

एम्स भोपाल की डॉ. मोहिनी बिंदा को राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार

भोपाल। एम्स भोपाल निरंतर चिकित्सा अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी क्रम में एनाटॉमी विभाग की सीनियर रेजिडेंट डॉ. मोहिनी बिंदा को सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमिस्ट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

डॉ. मोहिनी बिंदा को यह सम्मान उनके शोध कार्य के लिए मिला, जो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित मरीजों में होने वाले हिप फ्रैक्चर के आनुवंशिक पहलुओं पर आधारित है। यह शोध इस बात को समझने में महत्वपूर्ण है कि किन आनुवंशिक कारणों से हड्डियां कमजोर होती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। यह शोध कार्य डॉ. प्रशांत के मार्गदर्शन में किया गया। इस अध्ययन से भविष्य में हड्डियों से संबंधित बीमारियों की समय पर पहचान, रोकथाम और बेहतर उपचार संभव हो सकेगा। विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या अधिक देखने को मिलती है, ऐसे में यह शोध उनके स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निगम द्वारा जल परीक्षण, लीकेज सुधार एवं शिकायतों के निराकरण हेतु कार्यवाही निरंतर जारी

भोपाल। नगर निगम, भोपाल द्वारा शहर के नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु पानी की गुणवत्ता की जांच, लीकेज सुधार एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में निगम अमले ने शुक्रवार को विभिन्न झुग्गी बस्तियों सहित संपूर्ण शहर से जल के परीक्षण हेतु कुल 124 स्थानों से जल के नमूने लिये गये। निगम द्वारा 08 परीक्षण शालाओं के माध्यम से जल का परीक्षण किया जा रहा है। निगम अमले ने 52 स्थानों पर पाईप लाईनों के लीकेज सुधारे और सी.एम.हेल्पलाईन एवं महापौर हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में से 22 शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण ढंग से निराकरण किया गया।

महापौर श्रीमती मालती राय के निर्देश एवं निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के आदेश पर नगर निगम, भोपाल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दलों ने शहर की झुग्गी बस्तियों सहित संपूर्ण शहर में कुल 124 जल के नमूने लेकर गंध, रंग, स्वाद, रेसिडुअल क्लोरीन, पीएच, टरबीडिटी व बैक्टेरिया की जांच 08 परीक्षण शालाओं के माध्यम से कराई जा रही है। निगम अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 52 स्थानों पर पाईप लाईनों के लीकेज भी सुधारे और सी.एम.हेल्प लाईन, महापौर हेल्प लाईन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों में से 22 शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्ण ढंग से किया।

निगम अमले ने अभी तक झुग्गी बस्ती क्षेत्रों के 8192 स्थानों सहित शहर में कुल 17976 जल के नमूने लेकर 08 परीक्षण शालाओं के माध्यम से जल की गुणवत्ता की जांच कराई साथ ही 4485 लीकेज सुधारे। निगम अमले ने वर्तमान तक 12865 सीवेज चेम्बरों की सफाई कराई।

वित्त संचालनालय ने सभी विभागों को लिखा पत्र

मप्र के कर्मचारियों को मिल सकती है केंद्र की तरह सुविधाएं

भोपाल टुडे, भोपाल।

मप्र के कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिल सकती है। राज्य के साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को जल्द ही केन्द्र के कर्मचारियों के समान डेढ़ करोड़ रुपए का बीमा और रियायती दरों पर आवास, शिक्षा और पर्सनल लोन की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है।

मध्य प्रदेश के संस्थागत वित्त संचालनालय ने राज्य के कर्मचारियों को यह सुविधाएं दिए जाने के लिए सभी विभागों को पत्र लिखा है। पत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं का हवाला दिया गया है।

संस्थागत वित्त आयुक्त ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, नगरीय निकायों, विश्विद्यालय, बोर्ड, सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसमें कर्मचारियों को डेढ़ करोड़ रुपए तक का बीमा भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि किसी कर्मचारी की असमय दुर्घटना में मौत या इसमें स्थायी या आंशिक विकलांगता पर डेढ़ करोड़ तक का बीमा कवर दिया जाता है। इसके अलावा भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इस तरह की सुविधाएं राज्य के कर्मचारियों को मिल सके, इसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं।

कर्मचारियों को यह मिलेंगी सुविधाएं

प्रदेश के कर्मचारियों को भी केन्द्र के समान इस तरह की सुविधाए जल्द मिल सकती हैं। कर्मचारियों का अभी जीरो बैलेंस पर सैलरी अकाउंट तो खुलता है, लेकिन इसके साथ वह सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, जो केन्द्र के कर्मचारियों को मिलती है। हालांकि पत्र के बाद यह सुविधाएं प्रदेश के कर्मचारियों को भी जल्द मिलने की उम्मीद जागी है। इसमें यदि कोई कर्मचारी आवास लोन, एजुकेशनल लोन, वाहन के लिए लोन या फिर पर्सनल लोन लेता है, तो उसे कम ब्याज पर यह लोन मिल सकेगा। बैंक इस पर कर्मचारियों को रियायत देगी। इसके अलावा लॉकर खोलने पर भी कर्मचारियों को कम राशि देनी होगी, इसमें लगने वाले ऋण प्रसंस्करण शुल्क में उन्हें छूट मिलेगी। बैंक अकाउंट होल्डर कर्मचारी को डेढ़ करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया मिल सकता है। इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा और स्थायी या आंशिक विकलांगता के रूप में डेढ़ करोड़ का बीमा लाभ दिया जाएगा। एकाउंट होल्डर को टर्म लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त टॉपअप सुविधा के साथ 20 लाख रुपए तक का अधिक लाभ मिल सकेगा। बेस प्लान एवं अतिरिक्त टॉपअप सुविधा के साथ स्वयं और परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ मिल सकता है।

राजधानी में गर्मी शुरू होते ही जल संकट ने बढ़ाई परेशानी

झुग्गी बस्तियों में दो दिन में आ रहा टैंकर, दोपहर में लग रही लाइनें

भोपाल टुडे, भोपाल।

भोपाल में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत सामने आने लगी है। शहर के कई इलाकों में समय पर पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा असर झुग्गी बस्तियों में देखने को मिल रहा है, जहां रोजमर्रा के काम के लिए भी पानी जुटाना मुश्किल हो गया है।

नगर निगम की व्यवस्था भी कमजोर नजर आ रही है। कई इलाकों में पानी के टैंकर एक दिन छोड़कर पहुंच रहे हैं और उनके आने का कोई तय समय नहीं है। ऐसे में लोग सुबह से ही बर्तन लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कई परिवारों को पूरा पानी नहीं मिल पाता।

दोपहर की धूप में इंतजार, बढ़ी मुश्किलें: तेज गर्मी के बीच महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग दोपहर में टैंकर का इंतजार करते दिखाई देते हैं। झुग्गी बस्तियों में हालात और खराब हैं, क्योंकि वहां पानी का कोई स्थायी इंतजाम नहीं है। कई जगह बोरिंग बंद पड़ी हैं, जिससे लोग पूरी तरह टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं।

लोगों में नाराजगी, सुनवाई नहीं: स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। शिकायतों के बावजूद हालात में सुधार नहीं हो रहा, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी दिक्कत मई-जून में तापमान और बढने की संभावना है, जिससे पानी की मांग और बढ़ेगी। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जल संकट और गंभीर हो सकता है। यह समस्या अब सिर्फ एक-दो इलाकों तक सीमित नहीं, बल्कि शहर के कई हिस्सों में फैल चुकी है।

पानी की आपूर्ति और साफ-सफाई व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे: ऊर्जा मंत्री तोमर

ऊर्जा मंत्री शहर की सीवर, सफाई व्यवस्था देखने सुबह 6 बजे विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच

भोपाल।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार सुबह 6 बजे उप नगर ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर पेयजल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने सुबह 6 बजे वाटर सीवरेज पंपिंग स्टेशन पीएचई कॉलोनी में पहुंचकर नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ सीवरेज सफाई व्यवस्था देखी और जरूरी निर्देश दिए । ऊर्जा मंत्री तोमर ने वार्ड 4 के चद्र नगर, ठाकुर मोहल्ला, बार्ड 1 के रामाजी का पुरा, आरआर टॉवर पहुंचकर सीवर व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सड़क और विद्युत व्यवस्था तथा वार्ड 36 के गेंडे वाली सड़क और शिंदे की छावनी में पहले किये गये निरीक्षण के दौरान दिए निर्देश पर हुई कार्यवाही को देखा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम अधिकारियों को तुरंत सफाई व्यवस्था में सुधार करने हेतु निर्देशित किया।

सुपर सकर मशीन से सफाई कार्य का निरीक्षण

ऊर्जा मंत्री तोमर की पहल पर जनकल्याण समिति द्वारा नगर निगम के सहयोग से उप नगर ग्वालियर में सीवर लाइनों की सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियान के निरंतर 7 वें दिवस शुक्रवार को हजीरा चौराहे पर पहुंचकर सुपर सकर मशीन से चल रही सीवर लाइनों की सफाई के काम का भी निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से सफाई व्यवस्था और अधिक तेज, प्रभावी व सुदृढ़ बनेगी। उन्होंने कहा कि हमने सीवर सफाई के कार्य को अपने हाथ में लिया है और हम इसमें बदलाव लाकर दिखाएंगे। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि स्वच्छता, सुविधा और बेहतर जीवन स्तर बनाना हमारा संकल्प है।

नितिन नबीन की टीम में बढ़ेंगी महिलाएं...मप्र से कविता पाटीदार, हिमाद्री सिंह और भारती पारधी दौड़ में

महिलाओं को संगठन में मिलेगी महत्वपूर्ण पदों की कमान

भोपाल टुडे, भोपाल।

भाजपा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण पुरजोर वकालत कर रही है। विपक्ष ने भले ही लोकसभा में बिल के विरोध में वोट किया, लेकिन भाजपा आगे की तैयारियों में जुट गई है। वो अब संगठन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने जा रही है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में महिलाओं की भूमिका और संख्या बढ़ाने की कवायद तेज की जा रही है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, मप्र से राज्यसभा कविता पाटीदार, शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह और बालाघाट सांसद भारती पारधी के नाम चर्चा में हैं।

सूत्रों के मुताबिक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका स्पष्ट नजर आएगी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही (लगभग 15 मई तक) भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम घोषित होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में महिलाओं के हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी।

महासचिव-उपाध्यक्ष जैसे पदों पर मिलेगी कमान

नितिन नबीन की टीम में तीन महिला नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। उनकी टीम में 4 से 5 महिलाओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। 6 से 8 राष्ट्रीय सचिव पद महिलाओं को दिया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी महिलाओं की अग्रणी भूमिका रहेगी। नितिन नबीन की नई टीम में शामिल किए जाने वाली महिला राष्ट्रीय पदाधिकारियों में सभी क्षेत्रों का मिश्रण होगा। इसमें ग्रामीण, शहरी, महानगर, सेमी अर्बन, आदिवासी क्षेत्र और उत्तरपूर्वी भारत के महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। नितिन नबीन की टीम में शामिल किए जाने के लिए देशभर से दो दर्जन से ज्यादा महिलाओं का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है। राष्ट्रीय टीम में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के बाद विभिन्न प्रदेशों की टीम यानि प्रदेश पदाधिकारियों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी।

तीनों अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी

मप्र भाजपा की तीनों सांसद अपने-अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय और प्रभावी हैं। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को मालवा में ओबीसी का बड़ा चेहरा माना जाता है। कविता सुंदरलाल पटवा की सरकार में मंत्री रहे भेरूलाल पाटीदार की बेटी हैं। इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं शहडोल से लोकसभा सांसद हिमाद्री सिंह का बचपन ही राजनीतिक पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द गुजरा है। हिमाद्री सिंह के माता-पिता दलवीर सिंह और राजेश नंदिनी दोनों ही कट्टर कांग्रेसी रहे हैं। दोनों सांसद रह चुके हैं। 2017 में हिमाद्री सिंह भाजपा में शामिल हो गईं। जिसके साथ ही उनके राजनीतिक करियर ने भी एक नई उड़ान भरी, जो अब सतत ऊंचाइयों पर उड़ती ही जा रही है। वे लगातार दो बार से सांसद हैं। वहीं भारती पारधी पहली बार 2024 में सांसद बनी हैं। भारती पार्षद से सांसद बनी हैं। सूत्रों का कहना है कि मप्र से इन तीन महिला सांसदों के नाम पर चर्चा चल रही है।

जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण, मकानों की गणना ब्लाकों के गठन उपरांत प्रगणकों, पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण निरंतर जारी

भोपाल।

जनगणना-2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना कार्य हेतु नगर निगम भोपाल सीमा अंतर्गत आने वाले जोनल, चार्ज कार्यालयों में फील्ड ट्रेनर्स के माध्यम से प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण, मकानों की गणना ब्लाकों के गठन पश्चात विभिन्न चार्ज क्षेत्रों

में नियुक्त प्रगणकों, पर्यवेक्षकों को फील्ड ट्रेनर्स के माध्यम से सुचारू रूप से नियमानुसार प्रशिक्षण दिये जाने के क्रम में शुक्रवार को जोन क्र. 05 में फील्ड ट्रेनर्स डॉ. वसीम अंसारी व डॉ. आशीष भावलकर ने प्रशिक्षण दिया जबकि जोन क्र. 07 में डॉ. जे.एल.मालवीय, जोन क्र. 09 में फील्ड ट्रेनर डी.के. चैकसे एवं रमेश जैन, जोन 11 में प्रदीप सोनवाने एवं गौर गुप्ता तथा जोन 19 में वीरेन्द्र रनटेके एवं अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया।

खंडवा मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों ने सिखाये जीवन रक्षक गुर

एमपी ट्रांसको छैगांव में हुआ सीपीआर प्रशिक्षण

भोपाल टुडे,भोपाल।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस संभाग, बड़वाह की पहल पर छैगांव में जीवन रक्षक तकनीक सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में शासकीय मेडिकल कॉलेज, खंडवा के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्रतिभागियों को सीपीआर की सैद्धांतिक जानकारी के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया। इसमें आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया और प्राथमिक उपचार के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में एमपी ट्रांसको के खंडवा, छैगांव, बड़वाह एवं जुलवानिया क्षेत्र के लगभग 80 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण में शासकीय मेडिकल कॉलेज टीम खंडवा के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हृदय रोग) डॉ. रणजीत बडोले तथा डॉ. अनिल मंसारे ने विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सीपीआर की सही तकनीक, समयबद्धता और सावधानियों की जानकारी दी।

एंकर | 3 लाख किसानों से 12.94 लाख मीट्रिक टन खरीदी

गेहूं खरीदी क्षमता 2250 क्विंटल प्रतिदिन प्रति केंद्र बढ़ी

भोपाल टुडे, भोपाल।

मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी तेजी से जारी है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रति उपार्जन केंद्र प्रतिदिन स्लॉट बुकिंग की क्षमता बढ़ा दी है। अब किसान एक दिन में पहले से अधिक मात्रा में अपनी फसल बेच सकेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में अब तक 3 लाख 5 हजार 422 किसानों से 12 लाख 94 हजार 497 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके बदले एक लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1333 करोड़ 30 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। मंत्री ने बताया कि इस बार बड़ी संख्या में किसान गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करा रहे हैं। अब तक 7 लाख 33 हजार किसानों ने करीब 30 लाख 52 हजार मीट्रिक टन गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक किए हैं। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने प्रति उपार्जन केंद्र स्लॉट बुकिंग क्षमता पहले 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 1500 क्विंटल की थी। अब इसे फिर बढ़ाकर 2250 क्विंटल प्रतिदिन प्रति केंद्र कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की उपज समय पर खरीदी जा सके।

प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए कुल 3171 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्रों पर बैठने के लिए छायादार स्थान, पीने का पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा केंद्रों पर बारदाना, तौल कांटे, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट और गुणवत्ता जांच उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। उपज की सफाई के लिए पंखे और छननी जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। राज्य सरकार इस साल किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद रही है। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष गेहूं खरीदी के लिए रिकॉर्ड 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में 3 लाख 60 हजार अधिक है। सरकार ने इस साल 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है और अब तक खरीदे गए गेहूं में से 9 लाख 69 हजार 615 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है।

अब 26 अप्रैल तक भर सकेंगे आवेदन

10वीं-12वीं द्वितीय परीक्षा के फॉर्म की तारीख बढ़ी

भोपाल टुडे, भोपाल।

मध्यप्रदेश के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। मंडल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं।

मंडल ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 निर्धारित थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे में उन्हें एक और अवसर देने के लिए यह समय बढ़ाया गया है, जिससे कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित न रह जाए।

ऑनलाइन ही होगी पूरी प्रक्रिया: मंडल के सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन ही रहेगी। छात्र एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को आवेदन करते समय सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने होंगे।

नियम और दिशा-निर्देश पहले जैसे ही लागू रहेंगे: मंडल ने स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, जबकि परीक्षा से जुड़े अन्य सभी नियम, पात्रता और दिशा-निर्देश पूर्ववत ही लागू रहेंगे। छात्रों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही आवेदन करना होगा।

संपादकीय

दीदी जाने वाली है भाजपा आने वाली है?

भारत में आजादी के बाद पहली बार मतदान का एक ऐसा रिकॉर्ड बना है, जो ना भूतो ना भविष्यति की तरह है। प्रथम चरण के मतदान के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है, प्रथम चरण की जिन 154 सीटों में जो मतदान हुआ है उसमें बीजेपी 120 सीटों पर जीत रही है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव का नॉरेटिव बनाकर महिला आरक्षण बिल को आधार बनाकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। चुनाव के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन और जनगणना के मुद्दे पर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया था। बिल को महिला आरक्षण से जोड़कर प्रचारित किया गया। महिला आरक्षण बिल अस्तित्व में है। इसके बाद भी जब यह बिल संसद से दो तिहाई बहुमत से पास नहीं हो पाया। उसके बाद भाजपा ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का मुद्दा बनाया। महिला आरक्षण के नाम पर बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार किया। जो मतदान हुआ है, उस पर भाजपा का दावा है, महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़कर मतदान किया है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 86 फ़ीसदी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तमिलनाडु में भी महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है, यह दावा भाजपा द्वारा किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के पहले, इसी तरह का नॉरेटिव बनाकर भाजपा अप्रत्याशित रूप से चुनाव जीतती रही है। इस बार भी भाजपा को भरोसा है, वह पश्चिम बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही हैं। ठीक इसके विपरीत ममता दीदी का दावा है। इस बार महिलाओं ने एसआईआर के नाम पर जिस तरह से करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। तार्किक विसंगति के नाम पर लगभग 64 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग किए गए हैं। बंगाल के मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए पिछले 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। प. बंगाल के करोड़ों मतदाता इस प्रक्रिया में काफी परेशान थे। अंतोगत्वा 34 लाख से ज्यादा मतदाताओं को प. बंगाल में मतदान से वंचित रखा गया है। इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया बंगाल में हुई है। मतदाताओं को अपनी नागरिकता बचाने के लिए जो परेशानी उसे हुई है। बंगालियों को जिस तरह से परेशान किया गया है। उससे नाराज मतदाताओं ने इस बार टीएमसी के पक्ष में मतदान किया है। बंगाली स्मिता और नागरिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा के मतदाताओं ने भी टीएमसी के पक्ष में मतदान किया है। ममता बनर्जी का दावा है, भारी संख्या में जो मतदान हुआ है। वह एसआईआर के विरोध और बंगाली अस्मिता को बचाए रखने के लिए हुआ है। ममता बनर्जी का दावा है, वह भारी बहुमत के साथ चौथी बार अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। बंगाल चुनाव पर गहरी नजर रख रहे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, इस बार का विधानसभा चुनाव परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला होगा। पिछले 15 वर्षों के चुनाव परिणाम को देखने पर स्पष्ट है। कम्युनिस्ट विचारधारा के मतदाता प्रत्येक चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे थे। इसका मुख्य कारण कम्युनिस्ट विचारधारा का कमजोर होना और भाजपा द्वारा सुनयोजित रूप से बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना था। कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी के बीच में लगातार टकराव बढ़ने का फायदा भाजपा को पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार मामला उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से देश में घूसपेठियों के नाम बंगालियों को निशाने पर लिया गया है। उसके कारण बंगाली अस्मिता और एसआईआर के विरोध में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने भारी मतदान किया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के पहिले भय का वातावरण, चुनाव के पहले चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों एवं हिंदू कट्टरता के नाम पर बनाया गया उससे पश्चिम बंगाल का मतदाता नागरिक अधिकारों को लेकर सजग हुआ है। पहली बार वामपंथी विचारधारा को छोड़कर ममता दीदी के पक्ष में मतदान किया है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा परिवर्तन पहली बार होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का कमजोर होना पूंजीवादी व्यवस्था का मजबूत होना भाजपा के पक्ष में था। अब, जिस तरह से निम्न वर्ग नागरिकता, बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रहा है, उससे पश्चिम बंगाल का मतदाता भाजपा से भारी नाराज है। प्रथम चरण के मतदान में जिस शांति के साथ भारी संख्या में घरों से निकलकर मतदाताओं ने मतदान किया है। उससे यह संकेत मिल रहा है, इस बार पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ होने जा रहा है, जो भविष्य में प. बंगाल एवं देश की राजनीति को नई दिशा देगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश के चुनाव में जिस तरह के हालत थे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना के पक्ष में काम किया था। उसके बाद बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ी। एसआईआर के नाम पर लाखों मतदाताओं के वोट काटने की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में हुई है। बंगाली समुदाय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर अभी तक के हर मामले में मुखर रहता आया है।

विशेष

सुरक्षित जीवन की दिशा में: मलेरिया मुक्त भविष्य का संकल्प

सुनील कुमार महला

(25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस पर विशेष आलेख)

प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वास्तव में इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य मलेरिया जैसी जानलेवा, घातक और व्यापक संक्रामक बीमारी के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना, इसके रोकथाम के उपायों को प्रोत्साहित करना, समय पर जाँच एवं उपचार की व्यवस्था पर बल देना तथा वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयासों को गति देना है।

मलेरिया को आज भी एक सामान्य रोग समझ लिया जाता है, किंतु यह आज भी विश्व की सबसे गंभीर जनस्वास्थ्य समस्याओं में से एक है और हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह वायरस से नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में पहुँचता है।पाठक जानते होंगे कि हर मच्छर मलेरिया नहीं फैलाता।मलेरिया शब्द की यदि हम यहां पर बात करें तो यह शब्द इतालवी(इटली) भाषा के माला एरिया से बना है, जिसका अर्थ खराब हवा होता है, क्योंकि प्राचीन काल में लोग मानते थे कि यह बीमारी गंदी या दूषित हवा से फैलती है, जबकि बाद में विज्ञान ने सिद्ध किया कि इसका वास्तविक कारण मच्छर हैं।

पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि मलेरिया कोई नया नहीं बल्कि, यह एक अत्यंत प्राचीन रोग है, जिसका उल्लेख प्राचीन मिस्र, भारत तथा चीन के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। संक्रमित मच्छर के काटने पर प्लाज्मोडियम परजीवी रक्त में प्रवेश कर लाल रक्त कोशिकाओं में बहुगुणित होने लगता है, जिससे रक्तहीनता (एनीमिया), कमजोरी और अन्य जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। बहरहाल, इसके प्रमुख लक्षणों की यदि हम यहां पर बात करें तो इसके प्रमुख लक्षणों में क्रमशः तेज बुखार, ठंड लगना, कंपकंपी, सिरदर्द, मतली, उल्टी, अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, साँस फूलना, तेज नाड़ी, थकान, कमजोरी तथा जुकाम जैसी अनुभूति शामिल हैं। गंभीर अवस्था में रोगी मूर्च्छा तक में जा सकता है और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। कुछ लोगों में इसके लक्षण देर से प्रकट होते हैं, किंतु छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में यह शीघ्र और अधिक घातक रूप ले सकता है। रोगी के ठीक होने के बाद भी यह रोग पुनः हो सकता है। वर्षा ऋतु में या वर्षा के बाद जब घरों, गलियों और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा हो जाता है, तब मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है और संक्रमण का प्रसार बढ़ जाता है। यही कारण है कि स्वच्छता और जलभराव रोकना मलेरिया नियंत्रण का अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपाय माना जाता है। यह रोग मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, अमेरिका तथा अन्य उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होती है। मलेरिया गरीब क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं, सुरक्षित आवास और रोकथाम के संसाधनों की कमी होती है।

बहरहाल, यहां पाठकों को जानकारी देता चलूं कि वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में इसे मनाने का निर्णय लिया गया था और पहला आधिकारिक विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था।हर साल इस दिवस की एक थीम रखी जाती है और वर्ष 2025 की थीम- मलेरिया का अंत हमसे होगा- पुनर्निवेश करें, नए तरीके सोचें और प्रयासों को फिर से प्रज्वलित करें। रखी गई थी ,जिसका मतलब है कि मलेरिया का अंत हमारे अपने प्रयासों से ही संभव है। सरल शब्दों में कहें तो मलेरिया नियंत्रण और अनुसंधान में फिर से अधिक संसाधन, धन और ध्यान लगाना होगा,इस पर नियंत्रण के लिए हमें नए सिरे से सोचना होगा। हमें पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ नए, प्रभावी और आधुनिक उपाय अपनाने होंगे तथा मलेरिया उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा करना होगा। वहीं इस वर्ष यानी कि वर्ष 2026 में इसकी थीम-मलेरिया समाप्त करने के लिए प्रेरित- अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। रखी गई है। वास्तव में इसका सीधा सा संदेश यह है कि अवसर और साधन मौजूद हैं, इसलिए अब देरी नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई का समय है।

हाल फिलहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामले लगभग 28.2 करोड़ तक पहुँच चुके हैं और लगभग 6.10 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें अधिकांश पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। पूर्व की विश्व मलेरिया रिपोर्टों में यह तथ्य भी सामने आया कि कुछ वर्षों में हर 50 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु मलेरिया के कारण हो रही थी। वर्ष 2020 में विश्व स्तर पर 6,27,000 लोगों की मृत्यु मलेरिया के कारण दर्ज की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी।इन सभी के बीच राहत की बात यह है कि दुनिया के 47 देश मलेरिया मुक्त घोषित किए जा चुके हैं और चीन को भी मलेरिया मुक्त देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। वहीं पर, भारत की स्थिति पिछले वर्षों में उत्साहजनक रही है। देश ने एक दशक में मलेरिया मामलों में लगभग 80 प्रतिशत कमी दर्ज की है,यह काबिले-तारीफ है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत सरकार ने 2027 तक मलेरिया मुक्त भारत और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अतीत में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य मलेरिया से अधिक प्रभावित रहे, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत की लगभग एक चौथाई आबादी मलेरिया से प्रभावित बताई जाती है। 1935 के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत को मलेरिया के कारण प्रतिवर्ष भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। भारत सरकार ने 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया, जो अत्यंत सफल रहा, और 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। निरंतर सरकारी प्रयासों, चिकित्सा सेवाओं, दवाओं और जागरूकता अभियानों से रोगियों की संख्या में भारी कमी आई, किंतु अभी भी पूर्ण सफलता शेष है। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग, घर के आसपास पानी जमा न होने देना, जल टंकियों को ढककर रखना, खड़े पानी को सुखाना या बहाना, पानी की सतह पर तेल डालना जिससे लार्वा साँस न ले सके, नियमित साफ-सफाई, पूरी बाँह के कपड़े पहनना, समय पर जाँच, डॉक्टर की सलाह से दवा लेना तथा कीटनाशकों का छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है।

बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे कि सेनाओं और सुरक्षा बलों में मलेरिया रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनकी तैनाती प्रायः जंगलों, सीमावर्ती क्षेत्रों और मच्छर-बहुल स्थानों पर होती है, इसलिए मच्छरदानी का उपयोग वहाँ अनिवार्य माना जाता है। मलेरिया का उपचार कुनैन तथा आर्टिमीसिनिन जैसी दवाओं से किया जाता है। कुनैन सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। आरटीएस ,एसऔर आर-21 ऐसे टीके हैं जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी है और जिनसे विशेषकर बच्चों की सुरक्षा में सहायता मिली है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मच्छर नियंत्रण के लिए डीडीटी (डाइक्लोरो-डाइफेनाइल-ट्राइक्लोरोइथेन) कभी अत्यंत प्रभावी हथियार सिद्ध हुआ था। यह पहला आधुनिक कीटनाशक माना जाता है। इसका संश्लेषण 1874 में ऑस्ट्रिया के रसायनज्ञ ओथमार ज़ीडलर ने किया था तथा इसके कीटनाशी गुणों की खोज 1939 में पॉल हरमन मुलर ने की थी, जिन्हें 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों और आम जनता को मलेरिया तथा टाइफस से बचाने के लिए इसका व्यापक उपयोग हुआ। बाद में पर्यावरणीय प्रभावों के कारण इसके उपयोग पर नियंत्रण लगाया गया, किंतु कुछ परिस्थितियों में मलेरिया नियंत्रण हेतु सीमित उपयोग को स्वीकृति दी गई। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी, मच्छरों में कीटनाशक प्रतिरोधक क्षमता, परजीवियों में दवा प्रतिरोध, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, गरीबी, पर्याप्त कोष का अभाव, सामुदायिक भागीदारी की कमी, समय पर छिड़काव न होना, रोग की पहचान में देरी तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधा न पहुँच पाना मलेरिया उन्मूलन की बड़ी बाधाएँ हैं। इसलिए आवश्यक है कि जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, रेडियो, फिल्म, विद्यालयों और सामाजिक माध्यमों से जानकारी पहुँचाई जाए, गरीबों को स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, स्वच्छता पर बल दिया जाए और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। अंत में यही कहूंगा कि विश्व मलेरिया दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि सरकार, समाज, चिकित्सा संस्थान और प्रत्येक नागरिक सामूहिक संकल्प के साथ आगे आएँ, तो मलेरिया जैसी बीमारी को हराकर मलेरिया मुक्त भारत और मलेरिया मुक्त विश्व का सपना अवश्य साकार किया जा सकता है।

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।)

विशेष

मौत का मच्छर, लापरवाही का खतरा: मलेरिया पर निर्णायक वार का समय

श्वेता गोयल

- मुश्किल नहीं है मलेरिया को हराना

(विश्व मलेरिया दिवस (25 अप्रैल) पर विशेष)

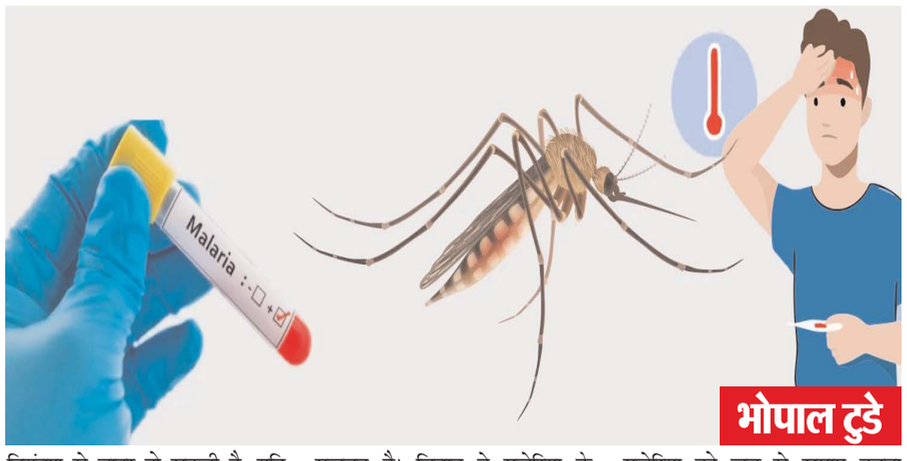

मलेरिया आज भी उन पुरानी और अत्यंत खतरनाक बीमारियों में से एक है, जो हर वर्ष लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और असंख्य परिवारों को शोक में डुबो देता है। यह एक ऐसा रोग है, जो पूरी तरह रोके जाने योग्य होने के बावजूद आज भी वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में मौजूद है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि मलेरिया से होने वाली अधिकांश मौतें छोटे बच्चों में होती हैं, विशेष रूप से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में, जो इस बीमारी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। मलेरिया का संबंध एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत घातक परजीवी से है, जो संक्रमित मादा एनोफेलीज मच्छर के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी रक्त में पहुंचकर पहले यकृत पर हमला करता है और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि मलेरिया केवल एक साधारण बुखार नहीं बल्कि शरीर की आंतरिक संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला रोग है।

वैश्विक स्तर पर मलेरिया की स्थिति आज भी चिंताजनक बनी हुई है। हाल के वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि हर वर्ष करोड़ों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 2024 में मलेरिया से लगभग 6.1 लाख मौतें इस बात का प्रमाण हैं कि यह बीमारी अभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है, यदि इसके प्रति जरा भी लापरवाही बरती जाए। यह केवल स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का भी प्रश्न है क्योंकि मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादकता घटाता है, स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ बढ़ाता है और गरीबी के चक्र को गहरा करता है। मलेरिया की सबसे खतरनाक विशेषता इसकी जटिलता और विविधता है। प्लाज्मोडियम के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से फाल्सीपेरम सबसे घातक माना जाता है। यदि इसका समय पर उपचार न किया जाए तो यह गंभीर एनीमिया, किडनी फेल्योर, मस्तिष्क संबंधी जटिलताओं और अंततः मृत्यु का कारण बन सकता है। यही कारण है कि मलेरिया के उपचार में देरी या लापरवाही सीधे जीवन के लिए खतरा बन जाती है। कई बार लोग शुरुआती लक्षणों को सामान्य बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर गंभीर परिणामों का कारण बनता है।

हालांकि आशा की किरण भी उतनी ही मजबूत है। विज्ञान ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नए टीकों का विकास, उन्नत दवाएं, कीटनाशक युक्त मच्छरदानियां और डिजिटल निगरानी प्रणाली इस दिशा में बड़ी प्रगति का संकेत हैं। मलेरिया के लिए विकसित कुछ टीकों ने यह साबित किया है कि मलेरिया को नियंत्रित करना अब केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता बन सकता है। कई देशों में इन टीकों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है और लाखों बच्चों को इससे सुरक्षा भी मिल रही है। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग मलेरिया संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में किया जा रहा है। इससे समय रहते रोकथाम के उपाय किए जा सकते हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों पर भी शोध जारी है, जिनके माध्यम से मलेरिया के प्रसार को नियंत्रित करने की संभावना तलाश की जा रही है। ये सभी प्रयास इस बात के संकेत हैं कि यदि वैश्विक समुदाय एकजुट होकर कार्य करे तो मलेरिया को जड़ से समाप्त करना संभव है।

इसके बावजूद, चुनौतियां कम नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और कीटनाशकों के प्रति मच्छरों की बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता इस लड़ाई को और कठिन बना रही है। तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण मच्छरों का फैलाव नए क्षेत्रों तक पहुंच रहा है, जिससे मलेरिया का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके अलावा, कई विकासशील देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, जागरूकता का अभाव और आर्थिक संसाधनों की सीमाएं इस बीमारी के नियंत्रण में बाधा बनती हैं। यही कारण है कि विश्व मलेरिया दिवस 2026 की थीम 'मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध- अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा' अत्यंत प्रासंगिक है। यह थीम केवल एक नारा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अब और देरी की गुंजाइश नहीं है। हमारे पास संसाधन हैं, तकनीक है और अनुभव भी है, आवश्यकता केवल दृढ़ इच्छाशक्ति और समन्वित प्रयास की है।

मलेरिया के लक्षणों में तेज बुखार, कंपकंपी, अत्यधिक पसीना, सिरदर्द, उल्टी और कमजोरी शामिल हैं। कई मामलों में यह रोग इतनी तेजी से गंभीर रूप ले लेता है कि मरीज को संभलने का अवसर तक नहीं मिलता। मलेरिया से बचाव के उपाय अत्यंत सरल लेकिन प्रभावी हैं। साफ-सफाई का ध्यान रखना, घर और आसपास पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी का उपयोग करना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना और समय-समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करना इस बीमारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से बरसात और गर्मी के मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक है,त्र क्योंकि यही वह समय होता है, जब मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है। किसी भी प्रकार के बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि तेज बुखार, ठंड लगना या अन्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच करानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार शुरू करना चाहिए। शुरुआती चरण में ही सही उपचार मिलने से मलेरिया को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है और गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।

सरकारों और स्वास्थ्य संस्थाओं की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, दूरस्थ क्षेत्रों में जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना, जागरूकता अभियान चलाना और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, समुदाय की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि बिना जनसहयोग के कोई भी स्वास्थ्य अभियान सफल नहीं हो सकता। वैश्विक स्तर पर मिली सफलताएं यह दर्शाती हैं कि यदि निरंतर प्रयास किए जाएं तो मलेरिया को नियंत्रित करना संभव है। कई देशों ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है और अनेक देश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह उपलब्धियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी इस दिशा में ठोस कदम उठाएं और मलेरिया मुक्त भविष्य की ओर बढ़ें।

मलेरिया के खिलाफ यह लड़ाई केवल चिकित्सा या विज्ञान की नहीं बल्कि जागरूकता, जिम्मेदारी और सामूहिक संकल्प की लड़ाई है। यदि हम समय रहते सावधानी बरतें, लक्षणों को नजरअंदाज न करें और उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न करें तो हजारों-लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। अब समय आ गया है कि हम इस बीमारी को एक सामान्य समस्या मानने की भूल न करें बल्कि इसे एक गंभीर चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए इसके उन्मूलन के लिए एकजुट हों। मलेरिया का अंत संभव है लेकिन इसके लिए हमें अपनी आदतों, नीतियों और प्राथमिकताओं में बदलाव लाना होगा। जब हर नागरिक जागरूक होगा, हर समुदाय सक्रिय होगा और हर सरकार प्रतिबद्ध होगी, तभी यह सपना साकार होगा। यह केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि मानवता के भविष्य का प्रश्न है। अब हमें यह तय करना है कि हम इस चुनौती के सामने झुकेंगे या इसे परास्त कर एक स्वस्थ, सुरक्षित और मलेरिया मुक्त विश्व का निर्माण करेंगे।

(लेखिका डेढ़ दशक से अधिक समय से शिक्षण क्षेत्र में सक्रिय शिक्षाविद हैं)

विचार

बंपर वोटिंग का संदेश: क्या ज्यादा मतदान सत्ता की वापसी का संकेत है या बदलाव की आहट–जनता की चुप्पी में छिपा जनादेश

कांतिलाल मांडोत

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और परिपक्वता को एक बार फिर रेखांकित किया है। भीषण गर्मी, लंबी कतारें और कई जगहों पर तनावपूर्ण माहौल के बावजूद जिस तरह मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वह सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी का सशक्त प्रदर्शन है।

यह सवाल अब स्वाभाविक रूप से उठता है कि इतनी भारी वोटिंग का अर्थ क्या है–क्या यह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जनसमर्थन का संकेत है या फिर परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक?

इतिहास बताता है कि अधिक मतदान को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कई बार ज्यादा मतदान सत्ता में बैठे दल के पक्ष में गया है, तो कई बार यह बदलाव की लहर का संकेत भी बना है। इसलिए इस बार भी केवल प्रतिशत के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जब सामान्य से कहीं अधिक मतदाता मतदान के लिए निकलते हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई मजबूत भावनात्मक या राजनीतिक कारण जरूर होता है।

पश्चिम बंगाल में इस बार मतदान का प्रतिशत 90त्न के पार चला गया, जो अपने आप में एक असाधारण स्थिति है। यहां चुनाव हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कभी-कभी हिंसक भी रहे हैं। इस बार भी छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का बड़ी संख्या में मतदान करना यह दर्शाता है कि वे अपने वोट के महत्व को समझते हैं और किसी भी परिस्थिति में लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। यहां मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, और दोनों ही दल इस भारी मतदान को अपने-अपने पक्ष में बता रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि यह मतदान उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों और कथित मतदाता सूची पुनरीक्षण (स्ट्रक्) के विरोध में जनता की प्रतिक्रिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे जनता की आवाज बताया है, जो उनके अनुसार बाहरी हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव के खिलाफ है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी इसे परिवर्तन की लहर के रूप में पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में दावा किया है कि जहां ज्यादा मतदान हुआ है, वहां भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है।

तमिलनाडु की स्थिति थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही रोचक है। यहां परंपरागत रूप से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच सीधी टक्कर रहती है। इस बार भी यही मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अभिनेता विजय की नई पार्टी ने समीकरणों को थोड़ा जटिल बना दिया है। रिकॉर्ड मतदान को यहां स्पष्ट जनादेश की संभावना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर तमिलनाडु में जब मतदान प्रतिशत बहुत अधिक होता है, तो मतदाता किसी एक पक्ष में स्पष्ट रूप से झुकाव दिखाते हैं।

इस बार के चुनावों में एक और महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कई क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। यह केवल संख्या का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का संकेत भी है। महिलाएं अब केवल मतदाता नहीं रहीं, बल्कि वे निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। उनके मुद्दे–महंगाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति–चुनावी विमर्श के केंद्र में आ चुके हैं।

अगर मुद्दों की बात करें तो दोनों राज्यों में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के मुद्दे प्रभावी रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोप, केंद्र-राज्य संबंध और पहचान की राजनीति प्रमुख मुद्दे रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में विकास, रोजगार, शिक्षा और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे विषयों ने मतदाताओं को प्रभावित किया है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों का असर भी दोनों राज्यों में साफ दिखाई देता है।

बंपर वोटिंग का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। जब लोग बड़ी संख्या में मतदान करने निकलते हैं, तो यह संकेत होता है कि वे मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं या फिर वे किसी बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। यह असंतोष भी हो सकता है और उम्मीद भी। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह मतदान किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह सामान्य चुनाव नहीं है।

राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन असली तस्वीर 4 मई को सामने आएगी जब नतीजे घोषित होंगे। तब यह स्पष्ट होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसे नकार दिया। फिलहाल, यह कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और असंतोष का प्रतिबिंब है।

अंततः, बंपर वोटिंग लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि जनता जागरूक है, सक्रिय है और अपने अधिकारों के प्रति गंभीर है। चाहे परिणाम कुछ भी हों, यह भागीदारी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

कमिश्नरेट व्यवस्था में नियुक्तियों का

मध्य प्रदेश, संवाददाता भोपाल में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अपनी ही कमजोरियों से जूझ रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था के दावे के बावजूद, अधिकारियों की भारी कमी इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को कम कर रही है। कमिश्नरेट सिस्टम में आईजी स्तर के नेतृत्व में से अधिक राजपत्रित अधिकारियों का प्रावधान किया गया है। लेकिन एक दर्जन महत्वपूर्ण पद अब भी खाली हैं। जोन-1 में डीसीपी का पद पिछले पांच महीनों से खाली है। जोन-3, जो संवेदनशील माना जाता है, में ढाई साल से स्थायी डीसीपी की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इन जोन में लूट, हत्या और गोलीबारी जैसी गंभीर घटनाएं हुई हैं। रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है। अतिरिक्त प्रभार मिलने से अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। अब तक की स्थिति इसी रूप में सामने है।

हवा की सफाई का दावा, सांस की समस्याएं बढ़ीं

मध्य प्रदेश रिपोर्टर इंदौर में हवा साफ दिख रही है, फिर भी सांस से जुड़ी बीमारियों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यह एक चौंकाने वाला सच है, खासकर जब इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। हालिया अध्ययन में पता चला है कि पारंपरिक प्रदूषण जैसे धूल और धुएं के बजाय, पराग‌कण और कबूतरों से जुड़े जैव-एरोसोल्स मुख्य कारण बन रहे हैं। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के डॉ. अंशुल तिवारी ने यह अध्ययन किया है। यह अध्ययन संस्था 'आरोग्यम' और नगर निगम के सहयोग से किया गया है। डॉ. तिवारी के अनुसार, वायु प्रदूषण की चर्चा आमतौर पर पीएम 2. 5 और पीएम 10 तक सीमित रही है। लेकिन अब जैव-एरोसोल्स जैसे पराग‌कण और कबूतरों की बीट भी समस्या बन रही है। इन जैव-एरोसोल्स के कारण लोग एलर्जी, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। हवा साफ दिखने के बावजूद यह खतरा बढ़ता जा रहा है। यह अध्ययन केवल राय पर आधारित नहीं है। इसमें 2019 से 2026 तक के वायु गुणवत्ता पैमानों के रुझान और शहरी निवासियों के सर्वेक्षण शामिल हैं। विशेषज्ञों ने कबूतरों और पराग‌कणों से जुड़ी श्वसन समस्याओं की पुष्टि की है। 90 प्रतिशत विशेषज्ञों का मानना है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक से पूरा मामला नहीं समझा जा सकता। अध्ययन में सप्तपर्णी और कोनोकार्पस जैसे वृक्षों की चिंताओं पर भी चर्चा की गई है। यह केवल हरियाली का मामला नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। डॉ. तिवारी ने सफाई प्रोटोकॉल और जनजागरूकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। मौसम आधारित चेतावनी और कम-एलर्जेन पेड़ों की सूची बनाना आवश्यक है। कबूतर-प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरत है। शहर में श्वसन रोगों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। कबूतरों और पराग‌कणों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह नागरिकों के स्वास्थ्य पर गहरा

जिलों में जाने वाले वक्ताओं ने उठाया

मध्य प्रदेश, संवाददाता

इंदौर में छह राज्यों के वक्ताओं की कार्यशाला संपन्न हुई। इसके बाद वक्ता प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं को तैयार करने का कार्य शुरू करेंगे। जनप्रतिनिधियों और नवप्रवेशी कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति समझाने के लिए प्रशिक्षण वर्ग अगले माह से लगेंगे। सात राज्यों के वक्ताओं की कार्यशाला में वरिष्ठ नेताओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली और गोवा के तीन सौ से अधिक वक्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। पहले इसे अप्रैल में करने का निर्णय लिया गया था। शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों के कारण अब यह मई से होगी। इंदौर में कार्यशाला की तारीख अभी तय नहीं हुई है। एक कार्यशाला में से नेता शामिल होंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी नवप्रवेशी मानकर प्रशिक्षित किया जाएगा। दैनिक भोपाल टुडे के संवाददाता की रिपोर्ट।

40 फीसदी उत्पादन में गिरावट, भारतीय चावल किसानों के सामने संकट

सीहोर समाचार डेस्क भारतीय कृषि श्रमिकों और चावल उत्पादन पर लू का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में इस खतरे का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, गंगा और सिंधु नदी के आस-पास के कृषि क्षेत्रों में सबसे अधिक खतरा है। इसके कारण उत्पादन में फीसदी से अधिक की गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट को विश्व पृथ्वी दिवस पर जारी किया गया। इसमें में भारत में हुई अत्यधिक गर्मी की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। अत्यधिक गर्मी ने कई राज्यों में फसलों और पशुधन को प्रभावित किया। यह विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल में गर्मी की घटनाएं बढ़ी हैं। भविष्य में यह कृषि प्रणालियों के लिए और भी अधिक खतरा है। अब तक सामने आए क्रम का निष्कर्ष यही है।

सरकार के दबाव में, पुलिस अधिकारी नहीं कर रहे काम

भोपाल से रिपोर्ट मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जितू पटवारी ने राज्य पुलिस और आईपीएस अधिकारियों को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। पटवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस की स्वतंत्रता सरकार के दबाव में आ रही है। फिलहाल दैनिक भोपाल टुडे की रिपोर्ट में सामने आया क्रम इसी बिंदु तक आता है।

पोषण पखवाड़े ने मातृ-शिशु जागरूकता बढ़ाई

इटारसी, संवाददाता इटारसी में 8वें पोषण पखवाड़े का समापन अप्रैल को हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मातृ एवं शिशु पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों के तहत किया गया। समापन कार्यक्रम रामगढ़ शाला, पुरानी इटारसी में हुआ। नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत और अनुविभागीय अधिकारी निलेश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। अन्य प्रमुख उपस्थितियों में शिक्षक आर. सोनकर, रमेश जगदेव, आदर्श मिश्रा और

सिंगरौली में पुरानी रंजिश से हुई हत्या का खुलासा

न्यूज डेस्क | मध्य प्रदेश सिंगरौली पुलिस ने हत्या के दो गंभीर मामलों में प्रभावी जांच के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। न्यायालय ने दोनों मामलों में मजबूत सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया। पहला मामला ग्राम बुढ़ेला का है, जहां बसंत शर्मा ने आलोक शर्मा की हत्या की। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने आलोक पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला दर्ज किया। घटनास्थल से सबूत जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में चालान पेश किया गया। दूसरा मामला लांघाडोल क्षेत्र का है। 15 मार्च 2024 को एक

रुपये के विवाद में किशोर की हत्या, हिंसा भड़की

करही में पैसे के विवाद में किशोर की मौत

न्यूज़ डेस्क, मध्य प्रदेश खरगोन के करही थाना क्षेत्र में रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। वर्षीय किशोर की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पैसों के लेनदेन को लेकर करही निवासी युवक और किशोर के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि किशोर को बेरहमी से पीटा गया। किशोर को गंभीर चोटें आईं और उसे करही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर किया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचते-पहुंचते किशोर की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर फैलते ही इलाके में तनाव बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी पक्ष के घर और

दुकान में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान तक पहुंचने लगीं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा ने घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल को मौके पर भेजा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अब तक

38 केंद्रों पर गेहूं खरीदी जारी, कलेक्टर ने दिए निर्देश

मध्य प्रदेश, संवाददाता ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने डबरा विकासखंड के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं

को सुना। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने केंद्रों पर छाया, पानी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। डबरा क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों पर कलेक्टर ने गेहूं तुलवाया। उन्होंने किसानों से भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने मोबाइल पर फीडबैक भी लिया। कलेक्टर ने सरला वेयर हाउस का भी दौरा किया। यहाँ उन्होंने ठंडे पेयजल और छायादार स्थान की आवश्यकता पर जोर दिया। फिलहाल दैनिक भोपाल टुडे की यह

समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन समाधान की बैठकें शुरू

मध्य प्रदेश रिपोर्टर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देश दिया है कि जिले की सभी नगरीय निकायों में स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए साप्ताहिक परिचर्चा बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य जनसमस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। परिषद के सदस्यों के साथ ये बैठकें हर सप्ताह होंगी। परियोजना अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी नगरीय निकायों के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। नगरीय निकाय नर्मदापुरम में बैठक होगी। दैनिक भोपाल टुडे न्यूज

इंदौर में बिजली कनेक्शन की जांच से मचा

इंदौर नगर निगम अब बिजली कनेक्शनों के सहारे संपत्तिकर बढ़ाने की योजना बना रहा है। एमओएस पर टैक्स लगाने के बाद निगम ने बिजली कंपनी से व्यावसायिक कनेक्शनों का डेटा जुटाया है। इस डेटा के आधार पर नगर निगम संपत्तियों की जांच शुरू कर चुका है। छोटे और बड़े घरों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान की जाएगी। नगर निगम जल्द ही अतिरिक्त संपत्तिकर की मांग कर सकता है। शहर में डेढ़ लाख से ज्यादा व्यावसायिक कनेक्शन हैं। बिजली कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, शहर में साढ़े सात लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से पांच हजार औद्योगिक कनेक्शन भी शामिल हैं। नगर निगम ने जोन के अनुसार डेटा का वितरण किया है। इससे संबंधित संपत्तियों के कर रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। उम्मीद है कि कई खाते मिलेंगे। ये खाते व्यावसायिक कनेक्शन के बावजूद घरेलू

आदेश वापस होने से प्रशासनिक प्रक्रिया

मध्य प्रदेश, संवाददाता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता के दो निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश वापस ले लिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की बेंच ने जारी किया। पूर्व प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने रजिस्ट्रार जनरल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन अब मामला आंतरिक प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक समिति को सौंपा गया है। सितंबर, को अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ग्वालियर खंडपीठ के

न्यायाधीश गुप्ता के आदेशों पर आपत्ति जताई थी। यह माना गया कि गुप्ता की टिप्पणियां जमानत के अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं। न्यायाधीश श्रीधरन की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट उन आदेशों को स्वयं नहीं

जनगणना में शामिल मृतकों के नाम ने बढ़ाई परेशानी

मध्य प्रदेश, संवाददाता

जिला प्रशासन और नगर निगम ने जनगणना के लिए कर्मचारियों की एक सूची बनाई है, जिसमें कई गंभीर गलतियाँ हैं। इसमें मृतकों, रिटायर हुए और तबादला हो चुके कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। हाल ही में हुए प्रशिक्षण सत्र में यह गड़बड़ी सामने आई। 700 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर चेतावनी दी गई। जब अधिकारियों ने संपर्क किया, तो पता चला कि कई कर्मचारी अब इस दुनिया में नहीं हैं या रिटायर हो चुके हैं। यह सब 2011 की जनगणना की सूची की कॉपी-पेस्ट से हुआ। सूची में सुधार कर दिया गया है। लेकिन अब कर्मचारियों की कमी हो गई है। फील्ड में काम कर रहे स्टाफ को दिक्कत हो रही है। नए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। 6 प्रगणकों

26 को होगा मुस्लिम जलसा

न्यूज रिपोर्टर | सीहोर भोपाल में अप्रैल को 'इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन जलसा' आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुस्लिम समाज में एकता और सौहार्द बढ़ाने के लिए है। कार्यक्रम कोहेफिजा स्थित एमआईजी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में होगा। समय दोपहर 1:50 बजे से 3:00 बजे तक रहेगा। इस जलसे में विभिन्न मसलकों के उलेमा एक मंच पर आएंगे। यह एकता का महत्वपूर्ण संदेश देने का अवसर है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के भीतर मतभेदों को समाप्त करना है। 'सिर्फ उम्मत' की सोच को आगे बढ़ाना है। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि मौलाना डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही विशेष अतिथि होंगे। वे समाज को एकता का संदेश देंगे। उनका मार्गदर्शन इस जलसे को विशेष बनाएगा। कार्यक्रम के बाद शाम को फतेहगढ़ इमामबाड़ा में ताजियती कार्यक्रम होगा। यह सभा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की स्मृति में होगी। आयोजक कार्यक्रम को संक्षिप्त और सारगर्भित रखने की योजना बना रहे हैं। मौलाना इलाही छोटा संबोधन देंगे। अनुवादक के माध्यम से संवाद होगा।

शुक्रवार रात ऐशबाग स्थित गरीब नवाज मस्जिद में जलसा-ए-शहादत हुआ। इस कार्यक्रम में तीखा आक्रोश देखने को मिला। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के पोस्टर जमीन पर रखकर विरोध जताया। उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। जलसे का माहौल गर्म था। लोग एकजुट होकर अपनी बात रख रहे थे। इस तरह के कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाते हैं। एकता और सौहार्द की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। भविष्य में ऐसे आयोजनों की और भी जरूरत है। जलसे में शामिल होने के लिए कई उलेमा को आमंत्रित किया गया है। इनमें से कुछ उलेमा समाज में एकता के पक्षधर रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में भाईचारा बढ़ता है। दैनिक भोपाल टुडे संवाददाता।

न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर गंभीर संदेश दिया

जबलपुर, संवाददाता उच्च न्यायालय ने नरसिंहपुर में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी रामलाल ठाकुर की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया ने कहा कि जघन्य अपराधों में सहायता करने वाले को भी समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। एकल पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति साझा मंशा से किसी अपराध में शामिल होता है, तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य आरोपियों के समान होती है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रामलाल ठाकुर पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग आदिवासी लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर बकौरी के जंगल में ले गया। वहां अन्य आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। यह वीडियो मामले में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम आया है। वीडियो में रामलाल ठाकुर की मौजूदगी स्पष्ट है। रामलाल ठाकुर को जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि उसने दुष्कर्म नहीं किया। उसका केवल सहयोग का मामला बनता है। बचाव पक्ष ने प्राथमिकी में देरी और शिनाख्ती परेड की अनुपस्थिति का हवाला दिया। उन्होंने अन्य सह-आरोपियों को जमानत मिलने का भी जिक्र किया। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता स्वाति जॉर्ज ने न्यायालय को बताया कि वीडियो में रामलाल ठाकुर की भूमिका स्पष्ट है। पीड़िता ने वीडियो के माध्यम से उसकी पहचान की। न्यायालय ने वीडियो साक्ष्य को ठोस माना। यह साक्ष्य आरोपी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण था। इससे उसकी भूमिका को साबित करने में मदद मिली। दैनिक भोपाल टुडे के संवाददाता की रिपोर्ट।

डेली कॉलेज चुनाव की प्रक्रिया में

मध्य प्रदेश रिपोर्टर डेली कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया के शेड्यूल जारी होने के बाद भी आपत्ति उठाई जा रही है। ओल्ड डेलियंस का आरोप है कि संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है। फिर भी चुनाव प्रक्रिया दिन की कर दी गई है। वर्ष में हुए चुनाव में प्रक्रिया दिन की थी। इस बार नियमों में बदलाव से विवाद गहरा गया है। ओल्ड डेलियंस ने कलेक्टर शिवम वर्मा और चुनाव अधिकारी रिटायर्ड जज सुशील गुप्ता को शिकायत की है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ओल्ड डेलियंस कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया से निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। पिछले वर्ष के चुनाव में कुछ नियम थे। सदस्यों को चुनाव कार्यक्रम के बारे में दिन पहले सूचित किया जाता था। सचिव नवीनतम पतों का उपयोग करके सदस्यों को जानकारी देते थे। इससे त्रुटियों को सुधारने का मौका मिलता था। चुनाव से दिन पहले नामांकन प्रपत्र वितरित किए जाते थे। यह एक

महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। दिन पहले मतपत्र इंदौर नगर पालिका सीमा के बाहर रहने वाले मतदाताओं को भेजे जाते थे। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम मतपत्रों पर लिख सकते थे। यह प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए आवश्यक थी। इस बार पूरी प्रक्रिया दिन की कर दी गई है। इससे चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। वोटरों को लुभाने में प्रत्याशी सक्रिय हैं। दोनों पक्षों की ओर से विवाद जारी है। प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया है। लोगों को फोन करके वोट देने की अपील की जा रही है। यह एक आम रणनीति है। चुनाव में विवाद और प्रचार का खेल जारी है।

पिछोर में आईपीएस को धमकाने पर चर्चा, लोधी की माफी

न्यूज़ डेस्क मध्यप्रदेश के पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी ने हाल ही में अपने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने पुलिस द्वारा अपने बेटे का जुलूस निकालने पर आहत होकर कुछ अपशब्द कहे थे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रीतम लोधी को तलब किया था। पार्टी से नोटिस मिलने के बाद विधायक ने अपने शब्दों पर खेद व्यक्त किया। इस मामले में विधायक प्रीतम लोधी की स्थिति काफी खराब हो गई थी। आईपीएस अधिकारी डॉ. आयुष जाखड़ को धमकाने का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा। पार्टी के दबाव के कारण लोधी ने अपने बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बेटे के जुलूस से वे बुरी तरह आहत थे। पार्टी ने उन्हें तीन दिन में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने भी लोधी से बंद कमरे में चर्चा की। बैठक के बाद लोधी ने मीडिया के सामने अपने शब्दों पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि कुछ शब्द गलत बोल दिए थे। लोधी ने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया। दैनिक भोपाल टुडे के संवाददाता की

पार्टी के भीतर चल रही चर्चा, लोधी पर गहरा असर

मध्यप्रदेश के पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी ने अपने अपशब्दों के लिए माफी मांगी है। उन्होंने आईपीएस डॉ. आयुष जाखड़ को धमकाने की घटना के बाद यह कदम उठाया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रीतम लोधी को तलब किया था। नोटिस मिलने के बाद उनके तेवर नरम पड़े हैं। पार्टी संगठन ने विधायक को तीन दिन में जवाब देने को कहा था। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष ने विधायक से बंद कमरे में चर्चा की। इस बैठक ने लोधी के बर्ताव में बदलाव लाया। विधायक ने मीडिया के सामने अपने शब्दों पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि कुछ गलत शब्द निकल गए थे। प्रीतम लोधी ने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया। उनका बीजेपी से तीन पीढ़ियों का जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि परिवार जनसंघ के जमाने से बीजेपी से जुड़े हैं। यह उनके लिए गर्व की बात है। बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में वे सहयोग करेंगे। उन्होंने इसके लिए सीएम को पत्र भी दिया। प्रीतम लोधी ने कहा कि बेटे का जुलूस निकालने से वे आहत हुए थे। उन्होंने पार्टी गाइडलाइन का ध्यान रखने की बात भी कही। लोधी ने कहा कि बेटे का जुलूस निकलने से मन आहत हो गया। इस पर उन्होंने कुछ गलत शब्द बोल दिए। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी को बुरा लगा तो खेद है। इस मामले में सफाई देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। पार्टी के लिए उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। वे अपने बेटे के खिलाफ जांच में पूरा सहयोग देंगे। यह घटना उनके लिए एक सबक है। भविष्य में वे और सावधानी बरतेंगे। पार्टी के भीतर प्रीतम लोधी की छवि पर असर पड़ा है। उनके बर्ताव से पार्टी को नुकसान हो सकता

पार्टी में लोधी की छवि को लगा गंभीर धक्का

विधायक प्रीतम लोधी ने अपने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि बेटे दिनेश लोधी का जुलूस निकालने से वे आहत हो गए थे। पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से बैठक की। लोधी ने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। ब्यूरो की रिपोर्ट।

नव विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

भोपाल। शाहजहांनाबाद इलाके में रहने वाली एक नव विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मर्ग कायम कर पुलिस कारणो की जॉच कर रही है। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अनीता कार्की पति राजन साउद (24) सनराइज कॉलोनी में दो महीने पहले ही किराए से रहने आए थे। दंपति की शादी तीन साल पहले हुई थी, उनका डेढ़ साल का बेटा भी है। बेटा फिलहाल नेपाल में स्थित ननिहाल में रहता है। इससे पहले उनका परिवार दिल्ली में रहता था। अनीता ब्यूटीशियन का काम करती थी, वहीं पति राजन साउद एक होटल में खाना बनाने का काम करता हैं। 22 अप्रैल की दोपहर करीब तीन बजे पति अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह बाथरुम गया इस बीच पत्नी ने कमरा बंद कर लिया। जब पति बाहर आया तो उसने पत्नि को पंखे पर दुपट्टे का फंदा बनाते हुए देखा। उसने काफी शोर मचाया और पत्नि को रोकने के लिये दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। लेकिन जब पत्नि नहीं मानी तब उसने दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले अनीता फंदे पर झूल चुकी थी। सूचना मिलने पर पहुचीं पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। जांच टीम का कहना है कि नवविवाहिता के मायके पक्ष के बयानों के बाद ही खुदकुशी का सही कारण साफ हो सकेगा जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जायेगी। मामला नवविवाहिता से जुड़ा होने के कारण इसकी जांच एसीपी शाहजहांनाबाद संभाग अनिल बाजपेयी करेंगें।

कटाई के बाद नरवाई को जलाने का समय नहीं, तकनीक अपनाएं

फसल अवशेषों को जलाने की बजाय, उन्नत यंत्रों से करें प्रबंधन, फसल को फायदा

मध्य प्रदेश रिपोर्टर कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि रबी फसल की कटाई के बाद नरवाई को जलाना नहीं चाहिए। इसके बजाय, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उन्नत कृषि यंत्रों और तकनीक का उपयोग करना चाहिए। बेलर मशीन का उपयोग फसल अवशेषों को एकत्र करने में किया जाता है। यह मशीन फसल अवशेषों को दबाकर और रस्सी से बांधकर एकत्र करती है। बेलर मशीन से पशु आहार और ईंधन के रूप में उपयोग करना आसान होता है। इससे कृषि कार्य में सहूलियत मिलती है। स्ट्रा रीपर एक अन्य मशीन है, जो फसल अवशेषों को काटती, श्रेस करती और साफ करती है। यह पशु चारा बनाने के लिए उपयुक्त है। इस मशीन को चलाने के लिए एच. पी. शक्ति के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर पी. टी. ओ. द्वारा चलित मशीनें उपयोग की जाती हैं। पहली मशीन मल्चर है, जो फसल अवशेषों को छोटे टुकड़ों में काटती है। इसे डिस्क हैरो मशीन से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। दूसरी मशीन हैप्पी सीडर है, जिसमें बुवाई की प्रणाली जुड़ी होती है। यह फसल अवशेष काटने और बुवाई दोनों कार्य करती है। तीसरी मशीन रोटरी डिस्क ड्रिल है। इसमें सॉयल रेजर डिस्क और बुवाई प्रणाली दोनों होती हैं। चौथी मशीन रोटावेटर है, जो खेत तैयार करने का मुख्य उपकरण है। इसमें एल या सी आकार के ब्लेड लगे होते हैं। स्ट्रिप टिल ड्रिल एक सक्रिय पीटीओ चलित बुवाई मशीन है। इसमें बीज बुवाई प्रणाली और जे प्रकार के ब्लेड होते हैं। रोटरी टिल ड्रिल एक पीटीओ चलित बुवाई मशीन है। इसमें रोटावेटर और बुवाई प्रणाली जुड़ी रहती है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि संयुक्त डिस्क हैरो एक भू-परिष्करण उपकरण है। इसमें आगे की डिस्क पी. टी. ओ. द्वारा चलित होती है। पीछे की डिस्क स्वतंत्र रूप से घूमती है। यह मिट्टी को समतल करने में मदद करती है। एमबी प्लाऊ मृदा की प्राथमिक जुताई के लिए मुख्य तंत्र है। यह फसल अवशेषों को गहराई में दबाने में सक्षम है। जीरो टिल ड्रिल ट्रैक्टर से खींची जाने वाली बुवाई मशीन है। यह बिना जुताई के फसल की सीधी बुवाई करती है। बेलर मशीन एक घंटे में हैक्टेयर खेत में बंधाई कर देती है। इसकी डीजल खपत लगभग लीटर प्रति घंटा होती है। नरवाई को जलाने के बजाय पशु आहार और ईंधन के रूप में उपयोग करें। इससे बचत होगी और पर्यावरण को नुकसान कम होगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलता है। इसके लिए उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क करें। कृषि यंत्रों का उपयोग फसल प्रबंधन में सहायक होता है। यह किसानों के लिए लाभदायक होता है। नरवाई को जलाना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। फसल अवशेषों का सही प्रबंधन आवश्यक है। यह भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। कृषि यंत्रों की मदद से खेती में सुधार हो सकता है। यह उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। किसान तकनीक का उपयोग करके अपने फसल प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं। यह उनके लिए फायदेमंद है। फसल अवशेषों का सही प्रबंधन करने से कृषि में स्थिरता आती है। यह दीर्घकालिक फायदों का स्रोत है। कृषि यंत्रों का सही उपयोग किसानों की आय बढ़ा सकता है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है। यह कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद करता है। किसानों को तकनीक के प्रति जागरूक होना चाहिए। इससे वे बेहतर निर्णय ले सकेंगे। कृषि यंत्रों का उपयोग करने से कार्य में तेजी आती है। यह समय की बचत करता है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। इससे लाभ होगा। भविष्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेतावनी पत्र, सुरक्षा उपायों का पालन करें

न्यूज़ डेस्क प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूखे कुएं में उतरने से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी उन खतरों के बारे में चेतावनी देती है जो ऐसे कुओं में उतरने से उत्पन्न हो सकते हैं। सूखे कुएं में जहरीली गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती हैं। इन गैसों का संपर्क बेहोशी, घुटन और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। कुएं में ऑक्सीजन की कमी भी गंभीर समस्या है। सीमित स्थान में ऑक्सीजन का स्तर गिरने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कई बार पानी का अचानक भर जाना भी एक गंभीर खतरा है। यह स्थिति कुएं में उतरने वाले व्यक्ति की जान को जोखिम में डाल सकती है। कुएं में उतरने से पहले सुरक्षा के लिए लालटेन रस्सी से नीचे डालें। यदि लालटेन बुझ जाए, तो इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीजन की कमी है। यदि कोई व्यक्ति सूखे कुएं में गिरता है, तो तुरंत बचाव के कदम उठाने चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई और व्यक्ति वहां न जाए। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। बिना उचित प्रशिक्षण और उपकरणों के कुएं में उतरने का प्रयास न करें। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सूचित करें। उन्हें दुर्घटना का स्थान और स्थिति की जानकारी दें। कुएं के आसपास के क्षेत्र को खाली कराएं। इससे अन्य लोग खतरे में नहीं पड़ेंगे। यदि संभव हो, तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की स्थिति का आकलन करें। उनकी चेतना, सांस लेना और चोटों की स्थिति देखें। आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने पर एक सुरक्षित बचाव योजना बनाएं। यह योजना प्रभावी और सुरक्षित होनी चाहिए। बचाव कार्य केवल प्रशिक्षित दल द्वारा किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि सभी सुरक्षा उपकरण मौजूद हों। अब तक की स्थिति इसी रूप में

ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है बेहोशी और मौत

सूखे कुएं में उतरने से कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यह समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कुएं में उतरने से पहले कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बेहोशी और मृत्यु का कारण बन सकती हैं। कुएं के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी एक गंभीर समस्या है। सीमित स्थान में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कई बार पानी अचानक भर जाने से भी दुर्घटनाएं होती हैं। इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। लालटेन का उपयोग करें। यदि लालटेन बुझ जाए, तो कुएं में उतरना खतरनाक है। बचाव के लिए तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। उन्हें स्थिति की जानकारी दें और क्षेत्र को सुरक्षित करें। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की स्थिति का आकलन करें। सुनिश्चित करें कि वह चेतन है या नहीं। प्रशिक्षित बचाव दल ही बचाव कार्य करें। उन्हें उचित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ब्यूरो की रिपोर्ट।

मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का बजट 100 करोड़, प्रस्ताव अरबों

मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मिली 100 करोड़ की मंजूरी, अरबों के प्रस्तावों में उलझन

ग्वालियर, न्यूज़ डेस्क मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का बजट करोड़ रुपये है, लेकिन प्रशासन के पास अरबों रुपये के प्रस्ताव पहुंचे हैं। यह योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों से प्रस्ताव आए हैं, जिनकी कुल लागत अरबों रुपये तक पहुंच गई है। कई जिलों ने एक-एक गांव के लिए करोड़ों रुपये के प्रस्ताव भेजे हैं। योजना की मूल भावना और बजट के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। पंचायतीराज विभाग इन प्रस्तावों का परीक्षण कर रहा है ताकि योजना को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले वर्ष इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य हर जिले में एक आदर्श ग्राम विकसित करना है। गांवों का चयन जनसंख्या और गोवंश की संख्या के आधार पर किया जाएगा। जनसंख्या कम से कम दो हजार होनी चाहिए और गोवंश की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। योजना में गो-पालन, डेयरी विकास, जैविक खेती, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास की परिकल्पना की गई है। फिलहाल दैनिक भोपाल टुडे की रिपोर्ट में सामने आया क्रम इसी बिंदु तक आता है।

एमपीईएसबी भर्ती घोटाले ने अधिकारियों को घेरा

मध्य प्रदेश रिपोर्टर इंदौर के एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यूजीसी से ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों पर अधिकारियों का चयन किया गया। ग्वालियर नगर निगम के दो सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी इस गड़बड़ी में शामिल हैं। ये अधिकारी लंबे समय से काम कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने प्रमुख सचिव और निगमायुक्त को शिकायत दी है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की जांच कराने और भर्ती को निरस्त करने की मांग की है। दस्तावेजों का खुलासा सूचना का अधिकार के तहत मिला है। यह जानकारी बेहद चौंकाने वाली है। 2022 में ग्वालियर नगर निगम में काबिल सिंह राजौरिया और अभिषेक मिश्रा को नियुक्त किया गया था। इनकी भर्ती प्रक्रिया में राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और संघाई

इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर के प्रमाण पत्र स्वीकार किए गए। ये दोनों यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इसलिए इनकी डिग्रियां अमान्य मानी जाती हैं। इंदौर नगर निगम में भी ऐसे अधिकारियों का चयन हुआ है। उनके दस्तावेज अभी तक उपल नहीं कराए गए हैं। जल्द ही इन अधिकारियों के नामों का खुलासा हो सकता है। ग्वालियर निगमायुक्त संघ प्रिय से जानकारी लेने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। सोनू गन्नोते ने बताया कि राजौरिया और मिश्रा की

धरपकड़ के बाद पुलिस ने तस्करों का जाल तोड़ा

न्यूज़ डेस्क

चंडीगढ़ में एक बड़ी हथियार तस्करी का नेटवर्क उजागर हुआ है। यह नेटवर्क मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सेल ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में हथियारों की तस्करी के बारे में जानकारी मिली। गुल्लू नामक आरोपी को सेक्टर-25 के रैली ग्राउंड के पास मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। उसने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे काबू किया। पूछताछ से पता चला कि गिरोह का संबंध इन दोनों राज्यों से है। हथियारों की सप्लाई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ट्राइसिटी तक होती थी। पुलिस ने हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। इनमें पिस्टल और सेमी-ऑटोमैटिक हथियार शामिल हैं। यह चंडीगढ़ में सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों की सबसे बड़ी बरामदगी है। मनीमाजरा निवासी राहुल और मोनू इस नेटवर्क में सक्रिय थे। मोनू, गुल्लू गुहाना का भांजा है। गिरोह केवल हथियार तस्करी तक सीमित नहीं था। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रंगदारी वसूली भी हो रही थी। लक्की पटियाल के नाम पर व्यापारियों से पैसे वसूले जा रहे थे। ड्रग्स तस्करों से भी मासिक उगाही का आरोप है। ऑपरेशन सेल अब रंगदारी नेटवर्क की जांच कर रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। गुल्लू गुहाना का भाई सन्नी गुहाना जेल में है। उसका नाम धनास में एक फायरिंग मामले में भी आया है। प्रारंभिक जांच में तस्करी का संगठित नेटवर्क सामने आया है। अन्य कड़ियों को जोड़ने का प्रयास जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला गंभीर है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इस गिरोह की गतिविधियाँ कई राज्यों तक फैली हुई हैं। जांच में और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। हथियारों की सप्लाई और रंगदारी वसूली के मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है। दैनिक भोपाल टुडे के संवाददाता की रिपोर्ट।

बलवा में नदी डूबने से तीन की जान गई

बड़ी, संवाददाता सेंधवा के पास वरला तहसील के ग्राम बलवा में एक ही परिवार के तीन भाई-बहन राधा, राजवीर और जयवीर की नदी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना गई। गुरुवार को तीनों बच्चों की अंत्येष्टि एक ही चिता पर की गई। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। हादसे के बाद परिवार गहरे सदमे में है। मां बार-बार बच्चों का नाम लेकर उन्हें पुकार रही है। पिता पवन खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। बच्चों की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बच्चे अपनी बड़ी बहन राधिका से मिलने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में वे नदी पर नहाने रुक गए। किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब बच्चे बहुत देर तक नहीं दिखे, तो खोजबीन शुरू हुई। नदी किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पले मिलीं। पवन ने तुरंत नदी में छलांग लगाई। उन्हें नदी में एक हाथ मिला, जिसे खींचने पर राधा का शव निकला। बाद में राजवीर और जयवीर के शव भी ग्रामीणों की मदद से निकाले गए। तीनों बच्चों को तैरना नहीं आता था। उन्हें गहराई का अंदाजा नहीं था। घटनास्थल पर नदी की गहराई करीब फीट थी। बच्चे से मिनट तक पानी में डूबे रहे। अंतिम संस्कार के समय क्षेत्रीय विधायक मोंटू सोलंकी भी उपस्थित रहे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया।

नकाबपोश बदमाशों ने युवक के घर के बाहर की हवाई फायरिंग

भोपाल से रिपोर्ट

भोपाल के श्यामलाहिल्स क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने सनसनी फैला दी। दो बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक के घर के बाहर हवाई फायरिंग की। यह घटना बुधवार रात हुई। बदमाश बिना नंबर की बाइक पर आए थे। उन्होंने पहले युवक का नाम चिल्लाया। इसके बाद दो राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद बदमाश भाग निकले। जिस युवक पर फायरिंग की गई, उसका नाम राजकुमार राजपूत है। राजकुमार का कुछ दिनों से एक बदमाश से विवाद चल रहा था। बदमाश पिछले कई दिनों से राजकुमार की तलाश कर रहा था। हैरानी की बात है कि दोनों ने थाने में समझौता किया था। राजकुमार और बदमाश दोनों श्यामलाहिल्स थाने से निकले थे। कुछ ही मिनटों बाद बदमाश राजकुमार के घर के बाहर पहुंचे। राजकुमार ने फायरिंग करने की शंका उस बदमाश पर जताई है। पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को घटना स्थल पर एक गोली का खोखा मिला है। थाना प्रभारी नीलम पटवा ने बताया कि आरोपितों की पहचान नहीं हो पाई है। राजकुमार प्राईवेट नौकरी करता है। उसकी मां शारदा बाई किलोल पार्क के पास रहती हैं। आकाश बाथम नामक युवक से राजकुमार का विवाद हुआ था। आकाश और उसके साथी राजकुमार को तलाश रहे थे। शारदा बाई ने इस मामले की शिकायत की थी। थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। बुधवार रात करीब 10:30 बजे दोनों पक्ष थाने में मौजूद थे। उन्होंने एक-दूसरे से समझौता किया था। थाने से निकलते ही बदमाशों ने फायरिंग की। राजकुमार के घर के बाहर यह घटना हुई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने फायरिंग की जांच शुरू की। घटना मुख्यमंत्री निवास के करीब हुई। यह क्षेत्र अतिसुरक्षित माना जाता है। इससे पहले भी अप्रैल को लूटपाट की घटना हुई थी। यह दूसरी गंभीर वारदात है। पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने निषेधाज्ञा लगाई थी। यह आदेश उसी क्षेत्र में लागू किया गया था। गोलीबारी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। पुलिस अब आरोपितों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। राजकुमार की मां ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। यह हमारे संवाददाता की रिपोर्ट है।

केजरीवाल का नया घर: कानूनी लड़ाई का मिला सकारात्मक नतीजा

दिल्ली, संवाददाता दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया बंगला प्राप्त किया है। यह बंगला लोधी एस्टेट में स्थित है। केंद्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के बाद केजरीवाल को यह आवास आवंटित किया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर नए घर में शिफ्ट होने की जानकारी साझा की। यह बंगला टाइप-7 श्रेणी का सरकारी आवास है। टाइप-7 बंगला आमतौर पर मंत्रियों या वीवीआईपी को आवंटित होता है। इस बंगले में चार बड़े बेडरूम और ऑफिस स्पेस है। बंगले में दो बड़े लॉन और तीन सर्वेंट क्वार्टर भी हैं। केजरीवाल को यह आवास 'आप' पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मिला। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास आवंटित नहीं होता। वे पहले सांसद अशोक मित्तल के घर में रह रहे थे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए आवास न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी ने टाइप-8 बंगले की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद केंद्र ने टाइप-7 बंगला आवंटित करने का निर्णय लिया। आवंटन की प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी। केजरीवाल ने नए बंगले में प्रवेश के बाद अपनी खुशी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आवास कानूनी प्रक्रिया के तहत मिला है। केजरीवाल ने कहा कि यह कोई विशेष रियायत नहीं है। उन्होंने बताया कि अब वे अपने परिवार के साथ नए घर में हैं। इससे पहले वे अस्थायी आवास में रह रहे थे। केजरीवाल ने अपने अधिकार की मान्यता को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया के तौर पर उनका अधिकार है। नए आवास में शिफ्ट होना उनके लिए एक नई शुरुआत है। यह कदम उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। आम आदमी पार्टी ने इस आवंटन को एक जीत बताया। केजरीवाल का नया पता अब '95, लोधी एस्टेट' है। यह आवास उनके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आवास के अधिकार को मान्यता मिलना महत्वपूर्ण है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आवास की स्थिति पर सवाल उठते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।' उन्होंने अपने नए आवास को लेकर खुशी व्यक्त की। यह बंगला उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत मिला है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्षों को आवास मिलना चाहिए। यह नियम सभी के लिए समान है। केजरीवाल ने अपने नए घर में प्रवेश करते हुए कहा, 'यह मेरे अधिकार की मान्यता है।' यह उनके लिए गर्व का क्षण है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा, 'यह जीत की तरह है।' पार्टी ने कानूनी लड़ाई में धैर्य रखा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देगा। इससे केजरीवाल की स्थिति मजबूत होगी। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास नहीं मिलता है। दैनिक

पहले चरण में बंगाल चुनाव में 85% वोटिंग

पश्चिम बंगाल रिपोर्टर कोर्ट ने उन लोगों को निर्देश दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, कि वे अपीलीय ट्रिब्यूनलों से संपर्क करें। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनलों से कहा कि वे पहले उन लोगों को सुनवाई का अवसर दें, जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल को कई याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इनमें लगभग चुनाव ड्यूटी अधिकारी शामिल थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कई अधिकारियों के नाम बिना कारण के हटा दिए गए। यह मनमाना निर्णय है। जस्टिस बागची ने कहा कि इस चुनाव में शायद वे वोट नहीं दे पाएंगे। बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ने की चार वजहें हैं। गुरुवार को हुए मतदान में महिला वोटर्स की संख्या अधिक रही। थर्ड जेंडर के वोटरों का प्रतिशत रहा। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि मतदान में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। इस चुनाव का भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया में सुधार हो रहा है। रिकॉर्ड मतदान से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। यह वोटिंग प्रतिशत नागरिकों की जागरूकता को दर्शाता है। महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिला वोटर्स ने मतदान किया। यह आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। इस बार थर्ड जेंडर के वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। थर्ड जेंडर ने वोट डाला। यह सामाजिक समावेश का संकेत है। राज्य में चुनावी हिंसा की कमी पर संतोष जताया गया है। इस समय मामला इसी बिंदु तक दर्ज है।

चारधाम यात्रा का समय, पर्यटकों की भारी भीड़

चारधाम की ओर बढ़ी भीड़, इंदौर की ट्रेनें फुल

मध्य प्रदेश रिपोर्टर

चारधाम यात्रा का उत्साह इस समय चरम पर है। लोग बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए बेताब हैं। पहले दिन ही केदारनाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर से चारधाम के लिए जाने वाले यात्रियों को ट्रेन की कन्फर्म सीटें नहीं मिल रही हैं। ट्रेनों में भीड़ के कारण समस्या बढ़ गई है। कुछ तारीखों की बुकिंग भी बंद कर दी गई है। इससे यात्रियों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम के कपाट खुलने के बाद इंदौर से बड़ी संख्या में यात्री जा रहे हैं। सभी जगहों पर यात्रियों की लम्बी कतारें देखी जा रही हैं। इंदौर से हरिद्वार के लिए दो ट्रेनें हैं। ये सप्ताह में दो बार चलती हैं, लेकिन सीटें नहीं मिल रही हैं। बुधवार और गुरुवार को उज्जैनी एक्सप्रेस चलती है। यह ट्रेन यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। शनिवार और रविवार को लक्ष्मीबाई नगर-ऋषिकेश ट्रेन चलती है। यह ट्रेन हरिद्वार से होकर गुजरती है। चारधाम यात्रा यहीं से शुरू होती है। दोनों ट्रेनों में मई-जून में लंबी वेटिंग है। दिन के बाद जैसे ही चार्ट खुलता है, वेटिंग शुरू हो जाती है। यात्रियों को सीटें मिलना मुश्किल हो जाता है। कई तारीखों की बुकिंग बंद हो गई है। 2, और मई को सेकंड एसी की बुकिंग फुल हो गई है। और मई को थर्ड एसी में भी रिग्रेट है। यह स्थिति यात्रियों के लिए निराशाजनक है। मई को स्लीपर में वेटिंग है। मई को थर्ड एसी में वेटिंग है। जून तक वेटिंग से

लेकर तक है। यह स्थिति चिंताजनक है। हर साल चारधाम यात्रा के लिए भारी भीड़ होती है। इंदौर से चल रही साप्ताहिक ट्रेन को हर दिन चलाने की मांग है। यात्री स्पेशल ट्रेन की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। उड़ानें बंद हो गई हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से देहरादून के लिए उड़ान नहीं है। दैनिक भोपाल टुडे संवाददाता।

अपर सचिव मंडलोई ने बंटवारे में किया बदलाव

उज्जैन से समाचार

मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़ा फेरबदल हुआ है। नई टीम में आइएएस कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सुधीर कोचर शामिल हुए हैं। एसीएस नीरज मंडलोई ने कामों का बंटवारा किया है। मंडलोई मुख्यमंत्री कार्यालय के मुखिया हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले सिंहस्थ को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी ली है। सचिव आलोक सिंह को कृषक कल्याण वर्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी पहले किसी के पास नहीं थी। सचिव कौशलेंद्र विक्रम सिंह को विजिलेंस शाखा का प्रभारी बनाया गया है। उनके पास गंभीर शिकायतों के निराकरण का भी दायित्व है। गुरुवार को से अधिक अफसरों को नए सिरे से जिम्मेदारियां दी गईं। इनमें अजात शत्रु श्रीवास्तव और राजेश हिंगणकर जैसे अधिकारी शामिल हैं। उप सचिव आदित्य कुमार शर्मा और अवर सचिव संदीप अष्ठाना को भी जिम्मेदारी दी गई है। आशीष कुमार और श्रीलेखा श्रोतिय को भी अलग-अलग कार्य सौंपे गए हैं। नीरज मंडलोई सीएम के सभी कामों का दायित्व संभालेंगे। आलोक सिंह सीएम कैबिनेट बैठक और भ्रमण कार्यक्रम देखेंगे। डॉ. इलैया राजा टी केंद्रीय मंत्री-सांसदों के पत्राचार का ध्यान रखेंगे। चंद्रशेखर वालिम्बे सीएम के भ्रमण कार्यक्रमों की तैयारी करेंगे। कौशलेंद्र विक्रम सिंह को निगरानी का बड़ा दायित्व मिला है। सुधीर कोचर को सीएम हेल्पलाइन का काम सौंपा गया है। चंद्रमौली शुक्ला निवेश से जुड़े कामों को देखेंगे। अरविंद दुबे प्रगति पोर्टल और परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीहोर में नए अफसरों की नियुक्ति से प्रशासन में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अफसरों की नियुक्ति से कामकाज में तेजी आएगी। नए अफसरों के अनुभव से प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। इससे जनता को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। कौशलेंद्र विक्रम सिंह का विजिलेंस शाखा में होना महत्वपूर्ण है। इस समय तक बात

सिंहस्थ को सफल बनाने का दायित्व मंडलोई ने लिया

मुख्यमंत्री कार्यालय में हालिया फेरबदल से प्रशासनिक ढांचे में नया बदलाव आया है। यह बदलाव के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने नए सिरे से कामों का बंटवारा किया है। उनके नेतृत्व में कई नए अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सचिव आलोक सिंह को कृषक कल्याण वर्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यह जिम्मेदारी पहले किसी अधिकारी के पास नहीं थी। कौशलेंद्र विक्रम सिंह को विजिलेंस शाखा का प्रभारी बनाया गया है। उन्हें गंभीर शिकायतों के निराकरण का भी कार्य सौंपा गया है। सीएम कार्यालय में से अधिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें कुछ पुराने और कुछ नए चेहरे शामिल हैं। सुधीर कोचर को उप सचिव के रूप में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रमों की तैयारी करनी है। चंद्रमौली शुक्ला को निवेश से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। वे उद्योगपतियों से सीधा संपर्क करेंगे।

युवकों की मौत पर उठे सवाल, पुलिस की सफाई पर विवाद

तीन युवकों की मौत के मामले में माइकल की गिरफ्तारी ने बढ़ाई जिज़ासा

न्यूज़ डेस्क | राज्य

शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र में 13-14 अप्रैल की रात तीन युवकों के शव कुएं में मिले। इस मामले में पुलिस ने आरोपी माइकल को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मृतकों की पहचान तनुज शुक्ला, सचिन सिंह बघेल और रोहित शर्मा के रूप में हुई थी। पुलिस का कहना है कि ये युवक गांजा तस्करी के दौरान भागने के प्रयास में कुएं में गिरे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी। युवकों के डूबने की भनक तक नहीं लगी। यह कई सवाल खड़े करता है। माइकल घटना की रात क्रेटा कार में ड्राइवर के बगल में था। इस कार को सुनील टांडिया चला रहा था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का मानना है कि माइकल गांजा नेटवर्क का अहम हिस्सा है। उससे पूछताछ में तस्करी के स्रोत के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। इस मामले में पहले शंकर विश्वकर्मा को पकड़ा गया था। उसके इनपुट पर आगे की कार्रवाई की गई। सुनील टांडिया, हीरासिंह, सोनू बैगा और रामपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया।

भोपाल के पास बन रहा नॉलेज एंड एआइ सिटी

भोपाल, संवाददाता

मध्यप्रदेश में एक नया शहर विकसित किया जा रहा है। इसे नॉलेज एंड एआइ सिटी के नाम से जाना जाएगा। यह शहर भोपाल की मौरी क्षेत्र में बनेगा। यहां लगभग एकड़ भूमि का उपयोग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के कैंपस होंगे। एआइ रिसर्च पार्क और डेटा सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। ग्लोबल एजेंसियों ने इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है। से अधिक एजेंसियों ने इसमें भागीदारी की इच्छा जताई है। नॉलेज एंड एआइ सिटी का निर्माण इंदौर-भोपाल कॉरिडोर के पास होगा। विस्तृत योजना अभी तय की जानी है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य एकीकृत

इकोसिस्टम बनाना है। यह इकोसिस्टम रिसर्च, स्टार्टअप, इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को जोड़ेगा। जिले में इस परियोजना को लेकर चर्चा जोरों पर है। रोडमैप पर एक महत्वपूर्ण सत्र भी आयोजित किया गया। ग्लोबल एजेंसियों की रुचि बढ़ रही है। अधिकारी इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्य एजेंसी को फाइनल करेंगे। एआई सिटी में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के कैंपस होंगे। दैनिक भोपाल टुडे संवाददाता।

तीन साल में हिंदी इंजीनियरिंग में छात्रों की कमी

भोपाल, संवाददाता

मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग पढ़ाई का सपना अधूरा रह गया है। इस पहल को शुरू हुए तीन साल हो चुके हैं, लेकिन छात्र संख्या में कमी बनी हुई है। सत्र 2022-23 से शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों पर छात्रों को हिंदी में पढ़ाना था। हालांकि, इस योजना के तहत केवल छात्रों ने ही दाखिला लिया है। यह आंकड़े इस योजना की हकीकत को दर्शाते हैं। इस पहल को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मंजूरी मिली थी। लेकिन कोई भी कॉलेज इसे पूरी तरह से लागू नहीं कर सका। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इस मामले में पीछे रह गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदी में इंजीनियरिंग शुरू करने के लिए जरूरी ढांचा तैयार नहीं किया गया। पाठ्यक्रम की कमी और विषय विशेषज्ञ प्राध्यापकों की कमी ने योजना को कमजोर किया। हर साल दाखिले की संख्या उम्मीद से कम रही है। वर्तमान सत्र

में करीब छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यह काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। इससे छात्रों को अध्ययन सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर का एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने हिंदी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शुरू की है। यहां सीटों पर छात्रों ने दाखिला लिया है। हिंदी में तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य सराहनीय है। लेकिन संसाधनों की कमी और अधूरी तैयारी ने इसे कमजोर बना दिया है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुए, तो यह योजना कागजों तक सीमित रह जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रयास जारी हैं। फैकल्टी की कमी को पूरा किया जा रहा है। पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई का लक्ष्य अब भी अधूरा है। दैनिक भोपाल टुडे के संवाददाता की रिपोर्ट।

28 स्टेशन और 2030 की मेट्रो योजना

भोपाल से रिपोर्ट

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के तहत ऑरेंज और ब्लू लाइन का काम तक पूरा होगा। भदभदा से रत्नागिरी मेट्रो लाइन में पहला स्लैब पिपलानी से जेके रोड के बीच डाला जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग डेढ़ किमी का स्लैब बिछाया जाएगा। अगले दो से तीन महीनों में इसे पुल बोगदा तक लाया जाएगा। भदभदा से डिपो चौराहा तक पियर्स का काम तेजी से चल रहा है। यहां भी इस साल के अंत तक स्लैब का काम शुरू होने की उम्मीद है। साल तक ब्लू लाइन का प्रतिशत काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑरेंज लाइन में भी काम तेजी से चल रहा है। ऑरेंज लाइन में एम्स से सुभाष ब्रिज तक छह स्टेशनों का काम पूरा किया गया है। अब ब्लू लाइन में रत्नागिरी तिराहा से ऐशबाग तक ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य है। तक ऑरेंज और ब्लू लाइन पर काम पूरा करना है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2027-28 तक का लक्ष्य लेकर चल रहा है। डिपो चौराहा से जहांगीराबाद तक की एलीवेटेड लाइन पर आपत्तियां आई हैं। सांसद आलोक शर्मा ने इसे वीआइपी क्षेत्र बताया है। विधायक आतिफ अकील ने बड़ा बाग की ओर मेट्रो लाइन पर आपत्ति जताई है। अब तक सामने आए क्रम का निष्कर्ष यही है।

श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा ४४।५°च

मध्य प्रदेश, संवाददाता

गर्मी के कारण राजस्थान के जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दौसा में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह बजे शुरू होंगे। बीकानेर, झुंझुनूं और जैसलमेर में सरकारी योजनाओं के काम के समय में भी बदलाव किया गया है। मजदूर अब सुबह बजे से दोपहर बजे तक काम करेंगे। केरल में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कन्नूर जिले में यह गर्मी से हुई मौत का पहला मामला है। कटक में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां अप्रैल तक बढ़ा दी गई हैं। रायगढ़ा, झारसुगुड़ा और गंजाम जिलों में अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में राजस्थान से आ रही गर्म हवा से तपिश बढ़ गई है। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम और सागर संभाग के शहरों में लू जैसे हालात हैं। शुक्रवार को जिलों में लू का अलर्ट रहेगा। नर्मदापुरम में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रदेश के मध्य हिस्सों में से अप्रैल के बीच लू चलने की संभावना है। जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में मजदूरों के काम करने पर रोक लगा दी गई है। कानपुर में एक व्यक्ति की लू से मौत हो गई। बिहार में जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया गया है। अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। राज्य सरकार ने दोपहर से बजे तक घर में रहने की सलाह दी है। पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अंधड़ और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में शुक्रवार से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। रांची, पलामू, धनबाद, जमशेदपुर में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के जिलों में बारिश की संभावना है। पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। गुजरात में राजकोट सबसे गर्म शहर रहा। गर्मी के कारण लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं। यह मौसम गर्मी के चरम पर पहुंच गया है। देशभर में हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। लोगों को गर्मी से बचने के उपायों की जरूरत है। मौसम में बदलाव की उम्मीद सभी को है। गर्मी से राहत पाने के लिए बारिश का इंतजार है। गर्मी का यह मौसम कई लोगों के लिए चुनौती बन गया है। गर्मी की लहर से लोग परेशान हैं। कई लोग घरों में कैद हो गए हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। राजस्थान में लू के कारण कामकाजी घंटे कम किए गए हैं। मजदूरों को सुबह जल्दी काम पर भेजा जा रहा है। इससे उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। कई लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं। सर्दियों में भीड़भाड़ वाले स्थान अब गर्मियों में भीड़भाड़ का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पानी की कमी हो गई है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जलाशयों की ओर जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते बारिश की संभावना जताई है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। तापमान में गिरावट की उम्मीद है। गर्मी के कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है। कई स्कूलों ने गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। इससे छात्रों को राहत मिलेगी। शिक्षकों को भी गर्मी से राहत मिलेगी। राजस्थान के किसानों को गर्मी का भारी नुकसान हो रहा है। फसलों की स्थिति चिंताजनक है। सरकार ने किसानों की मदद का आश्वासन दिया है। केरल में लू से हुई मौतों की संख्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गर्मी से निपटने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन खोली है। लोग फोन करके जानकारी ले सकते हैं। यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पंजाब में भी लू का असर बढ़ रहा है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। बच्चे घर पर रहकर सुरक्षित रहेंगे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। कई लोग एसी और कूलर की दुकानों पर जा रहे हैं। बिक्री में वृद्धि देखी जा रही है। हरियाणा में गर्मी से राहत के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। गर्मी के कारण सड़कें सुनसान हो गई हैं। लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं। यह स्थिति असामान्य है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर श्रमिकों पर पड़ रहा है। कई श्रमिक काम पर नहीं

राजस्थान में गर्मी के बाद बारिश की उम्मीद, 20 जिलों पर असर

थान, संवाददाता

जयपुर में मौसम विभाग ने राजस्थान में मौसम के बदलाव की सूचना दी है। जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले घंटों में अधिकांश जिलों में लू का असर देखने को मिला। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। पिलानी, चित्तौड़गढ़, फलोदी और बीकानेर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, और अप्रैल को हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा में बारिश की संभावना है। पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का असर जारी रहेगा। तापमान में से डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। बीकानेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में पारा से डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे मौसम में बदलाव की संभावना बन रही है। अप्रैल से हल्की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। और अप्रैल को मेघगर्जन और धूलभरी आंधी की संभावना है। इन जिलों में अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल हैं। जयपुर, झुंझुनूं, करौली और खैरथल में भी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दोपहर बाद चलने वाली तेज हवाएं मदद करेंगी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अस्थायी होगा। फिर भी, यह राहत भरा रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है। हीटवेव के दौरान बाहर निकलने से बचें। पर्याप्त पानी पिएं और हाइड्रेट रहें। किसानों और आमजन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है। आसमान से राहत की उम्मीद ने सुकून लाया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश से तापमान में कमी आएगी। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि आंधी की संभावना है। राजस्थान के कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, भरतपुर और दौसा में बारिश की संभावना है। इन जिलों में मौसम का बदलाव देखा जा सकता है। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे मौसम में बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है। और अप्रैल को बारिश की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें। बारिश से फसलों को लाभ होगा। लेकिन, आंधी से नुकसान की भी आशंका है। जयपुर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अब तक मामला

भाजपा की अनुशासित पार्टी वाली छवि पर खड़े हो रहे सवाल, सत्ता, संगठन और संघ के दिशा-निर्देश दरकिनार, अनुशासन, भाषा की गरिमा तार-तार

भोपाल टुडे, भोपाल।

मप्र में भाजपा सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों द्वारा अधिकारियों को धमकी देने और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

यह स्थिति तब है जब सत्ता, संगठन और संघ के सख्त दिशा-निर्देश है कि भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि अनुशासन, भाषा की गरिमा और आचरण पर विशेष ध्यान दें। यही नहीं पार्टी संगठन समय-समय पर नोटिस जारी करके इन घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार-बार दोहराई जा रही ऐसी घटनाओं ने भाजपा की अनुशासित पार्टी वाली छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। पार्टी का इस बात पर हमेशा फोकस रहता है कि उसके नेता और कार्यकर्ता अपनी हद में रहे। लेकिन मप्र में वरिष्ठ नेताओं के बिगड़े बोल और अधिकारियों को खुलेआम दी जा रही धमकियों ने पार्टी की किरकिरी कराई है। पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने करैरा के एसडीओपी (प्रशिक्षु आइपीएस) आयुष जाखड़ को खुलेआम धमकी दी। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इससे पहले विधानसभा के बजट सत्र में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। मई, 2025 में प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने एक सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वत-संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसी माह के शुरू में हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना के मामले में निर्देश जारी किए। उन पर अवैध उत्खनन मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट जज से संपर्क करने की कोशिश का आरोप है।

विधायकों की कार्यप्रणाली चिंताजनक

मप्र भाजपा के कुछ विधायकों ने पिछले कुछ समय के दौरान ऐसी हरकते की हैं, जो चिंताजनक है। सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बृजबिहारी पटैरिया ने एक मामले में पुलिस द्वारा डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने से नाराज होकर केसली थाने के भीतर ही अपना इस्तीफा लिख दिया और उसे विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। कुछ दिन पहले उनकी बेटी प्रियंका पटैरिया पर एक युवक के साथ जूते से मारपीट करने का आरोप लगा है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल एक वीडियो में एडिशनल एसपी अनुराग पांडेय के सामने दंडवत होते नजर आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी अपराधियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने अगस्त 2025 में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर मुक्का (घूंसा) ताना था और उन्हें चोर कहा था।

महिला आरक्षण पर एक-दूसरे को घेरने की तैयारी: महिला आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस में ठन गई है। दोनों ने एक-दूसरे को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिरते का ठीकरा भाजपा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर फोड़ रही है। 27 अप्रैल को होने जा रहे विस के एक दिवसीय विशेष सत्र में भाजपा की कोशिश यही रहेगी कि कांग्रेस को महिला विरोधी ठहराया जाए। इसकी काट में एक ओर जहां विस के भीतर कांग्रेस विधायक दल की ओर से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को बिना परिसीमन और जनगणना को ढाल बनाए लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा तो दूसरी ओर संगठन की तैयारी विधानसभा का घेराव करने की है। इस पर निर्णय एक-दो दिन में होगा। भाजपा और कांग्रेस, महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक-दूसरे को घेरने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने जहां कई स्तरीय कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना और उसमें कांग्रेस के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाना शामिल है।

न्यूज ब्रीफ

दसवीं बोर्ड टॉपर कु. प्रतिभा सोलंकी को प्रोत्साहनस्वरूप मिलेंगे एक लाख रुपये: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दसवीं बोर्ड की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली होनहार छात्रा पन्ना की कु. प्रतिभा सिंह सोलंकी को माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त करने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेटी कु. प्रतिभा और उनके माता-पिता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेटी कु. प्रतिभा को सुशासन की प्रतीक लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर माँ की मूर्ति भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भेंट तथा आशीर्वाद प्राप्त करने प्रतिभा, परिजन सहित समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) आईं थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिभा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रतिभा जैसी बेटियां प्रदेश की शान हैं। प्रतिभा की सफलता लाखों बेटियों और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। बिटिया की उपलब्धि पर पूरे प्रदेश को गर्व है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कु. प्रतिभा और उनके परिजन ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया।

नगरीय क्षेत्र की सीमा में पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों माधक पदार्थों का विक्रय प्रतिबंधित

भोपाल। रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों जैसे सहज उपलब्ध स्थान से रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है । विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ज्ञापनों, सामाजिक संगठनों व जनसामान्य से यह तथ्य प्रकाश में आया कि शहर में नाबालिकों/युवाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के नशे (चरस, गांजा आदि) के सेवन हेतु रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल का चलन बढ़ गया है जो कि मादक पदार्थ (चरस, गांजा आदि) को सुगमता से अपने साथ रखने, छुपाने व सेवन करने में आसान सरल है। इसमें टाईटेनियम ओक्साईड, पोटेशियम नाईट्रेट, आर्टिफिसल डाई, केल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरिन ब्लीच जैसे जहरीले पदार्थ पाये जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिये बेहद हानिकारक है। रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों जैसे सहज उपलब्ध होने वाले स्थानों में विक्रय किया जाने लगा है, जिससे सरलता से नाबालिकों युवाओं को उपलब्ध है। जिसके परिणामस्वरूप नाबालिकों/युवाओं में नशे की प्रवृत्ति तथा नशे में कारित अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जो उनके स्वयं व जन सामान्य के लिये गम्भीर खतरा बन सकता है। रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के उपयोग की रोकथाम की दृष्टि से इसके पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों जैसे सहज उपलब्ध स्थानों से विक्रय पर प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः भोपाल नगरीय क्षेत्र की सीमा में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों जैसे सहज उपलब्ध स्थान से रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।

चूंकि उक्त आदेश को जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल प्रभावशील किया जानाआवश्यक हो गया है, समय अभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो आगामी दो माह तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीयन्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

गुस्साई पत्नि मायके गई, अकेले रह रहे पति ने लगा ली फांसी

भोपाल। गुनगा थाना इलाके में स्थित ग्राम सुकलिया में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक हेमराज गिरी (35) निजी कंपनी में टॉवर लगाने का काम करता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा मासूम बेटी है। करीब पंद्रह दिन पहले हेमराज का पत्नी से विवाद हो गया था। विवाद के बाद गुस्साई पत्नी बच्ची के साथ मायके चली गई। करीब पंद्रह दिन से हेमराज घर में अकेला था। पड़ोस में उसके रिश्तेदार रहते हैं। रिश्तेदारों ने बताया कि गुरुवार सुबह हेमराज जल्दी सोकर उठा था।

दिल्ली से भोपाल आई सूची, दो दर्जन नेताओं के नाम फाइनल

निगम-मंडल की सूची का खत्म हुआ इंतजार!

भोपाल टुडे, भोपाल।

मप्र में चार आयोगों में राजनीतिक नियुक्ति के बाद अब निगम-मंडल की सूची जल्द आ सकती है। जानकारी के मुताबिक कई दौर की बैठकों के बाद इस सूची पर राष्ट्रीय नेतृत्व की मुहर लग चुकी है। निगम-मंडलों को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे नेताओं की आस पूरी हो सकती है।

पिछले दिनों सीएम ने भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक में जल्द नियुक्तियां होने के संकेत देते हुए कहा था कि निगम मंडलों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सदस्यों की नियुक्ति एक साथ की जाएगी। आज जारी दो आदेशों में अध्यक्ष के साथ सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। महिला और बाल संरक्षण आयोग में एक दो दिन में नियुक्ति के आसार हैं। वहीं जिन नेताओं के नाम चर्चा में हैं उनमें चेतन सिंह, विनोद गोटिया, संजय नगायच शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार सत्ता और संगठन के बीच चले लंबे मंथन और फिर उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक में दो दर्जन नामों पर सहमति बन चुकी है। इन नेताओं के नामों की सूची केन्द्रीय नेतृत्व को भेजी गई थी। वहां से हरी झंडी मिल चुकी है। बताया जाता है कि केन्द्रीय नेतृत्व ने सत्ता और संगठन से अपने हिसाब से निर्णय लेने को कहा है। निगम मंडल, प्राधिकरणों और आयोगों में नियुक्ति को लेकर लंबे समय से बैठकों का दौर चल रहा है। भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में भी यह मामला उठा था, तब राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा था कि इस मसले पर अध्यक्ष से बात करें। प्रदेश के दो दर्जन से अधिक निगम-मंडलों और विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। इनमें अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं।

आयोगों में हुई नियुक्ति: मप्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा हो गई है। पूर्व विधायक कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं सदस्यों के तौर पर रामलाल मालवीय और बारेलाल अहिरवार के नाम हैं। जाटव अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व विधायक रामलाल रौतेल की नियुक्ति की गई है। रौतेल दूसरी बार ये पद संभालने जा रहे हैं। इससे पहले 2010 में उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वे दो बार अनूपपुर सीट से विधायक रहे और कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आयोग के सदस्य के तौर पर भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे के नामों का ऐलान हुआ है। इसके अलावा राज्य महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। एक या दो दिन में ऐलान होने की संभावना है। इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग के लिए भी अध्यक्ष और सदस्यों के नाम पर सहमति बन चुकी हैं। डॉ. निवेदिता शर्मा को अध्यक्ष बनाया जाएगा। वो पहले से ही बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। उनके अलावा सोनम निनामा, अर्चना गुप्ता, मोनिका बट्टी और सीमा सिंह को सदस्य बनाने पर सहमति बनी है।

नामों को लेकर सीएम-अध्यक्ष में चर्चा

निगम मंडल की जो सूची फाइनल हुई है, उसमें 32 नाम होने की चर्चा प्रदेश भाजपा कार्यालय में सरगर्म है। कई दावेदार प्रदेश कार्यालय के सम्पर्क में रहे। संगठन के एक नेता ने बताया कि दो दर्जन निगम मंडल और प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय हो चुके हैं। सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसे लेकर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच एकांत में लंबी चर्चा का दौर चला। दोनों नेताओं के बीच हुई मंत्रणा से दावेदारों की उम्मीदें जग गई है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा को सत्ता में रहते हुए मध्य प्रदेश में दो दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है।

सीएम सचिवालय में अफसरों के काम का नया बंटवारा

सिंहस्थ से राजनीतिक नियुक्तियों तक तय हुई जिम्मेदारियां

भोपाल।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों के बीच कामकाज का नया बंटवारा किया। नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों और कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि सचिवालय का काम अधिक सुचारु रूप से चल सके। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई को समन्वय से जुड़े मामलों, ट्रांसफर संबंधी फाइलों, सिंहस्थ से जुड़ी ए-प्लस नोटशीट और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही इंदौर और उज्जैन संभाग से जुड़े मामलों की निगरानी भी वे करेंगे।

सचिव आलोक कुमार सिंह को सरकारी और गैर-सरकारी नियुक्तियों, सांसदों और विधायकों से जुड़े कार्यों के साथ कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग से जुड़े मामलों को भी वे देखेंगे। सचिव टी इल्याराजा को केंद्र सरकार और दिल्ली से जुड़े मामलों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। वे केंद्र के साथ तालमेल और लंबित विषयों पर काम करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ किए गए कौशलेंद्र विक्रम सिंह को विभिन्न विभागों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा वे सीएम कार्यालय की विजिलेंस शाखा, सरकार के संकल्प पत्र की मॉनिटरिंग, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, विधायक डैशबोर्ड और आईटी सेल की देखरेख करेंगे।

महिला स्व-सहायता समूह की सराहनीय पहल

मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने के संकल्प के साथ आटे के दीपक का शुरू किया व्यवसाय

भोपाल टुडे, भोपाल।

प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं उनकी आय में वृद्धि के उद्देश्य से स्व-सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है। प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार के साधन अपना रहे हैं। ओंकारेश्वर के एक स्व-सहायता समूह ने इसी दिशा में एक अच्छा कार्य आरंभ किया है।

खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर के समीप स्थित ग्राम मोरटक्का निवासी श्रीमती विजया जोशी ने मां नर्मदा आजीविका स्वयं सहायता समूह का गठन कर

एक अनूठी पहल की। उन्होंने आटे के दीपक निर्माण का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि प्लास्टिक के दोने में दीपदान करने से नदी में प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मां नर्मदा में रहने वाले जलीय जीव-जंतुओं को भी नुकसान होता है। इसी सोच के साथ समूह की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आटे के दीपक बनाने का कार्य शुरू किया।

सरकारी सहयोग और बाज़ार उपलब्धता से महिलाओं को मिली नई पहचान: महिलाओं ने स्व-सहायता समूह के माध्यम से डेढ़ लाख रुपये का ऋण लेकर दीपक निर्माण की मशीन खरीदी। ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक आनंद शर्मा ने बताया कि मिशन द्वारा महिलाओं को पैकेजिंग, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के क्षेत्र में आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए आटे के दीपक मोरटक्का के खेड़ीघाट स्थित फूलमाला एवं किराना दुकानों पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इससे ओंकारेश्वर और मोरटक्का क्षेत्र में मां नर्मदा में दीपदान करने वाले श्रद्धालुओं को उचित मूल्य पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प मिल रहा है।

समूह की अध्यक्ष श्रीमती विजया जोशी ने बताया कि इस पहल से दो प्रमुख लाभ हुए हैं। पहला, प्लास्टिक के दोने से होने वाला प्रदूषण कम हुआ है। दूसरा, दीपक में उपयोग किया गया आटा नदी में मछलियों के भोजन के रूप में उपयोग हो रहा है।

कृषि चौपाल के माध्यम से प्रदेशभर में किसान जागरूकता अभियान

नरवाई जलाना खेत और सेहत दोनों के लिए हानिकारक: कृषि मंत्री कंषाना

भोपाल टुडे, भोपाल।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि प्रदेश में नरवाई जलाने के नुकसान और नहीं जलाने के फायदों को लेकर कृषि विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप 'कृषि चौपाल' के माध्यम से हर विकासखंड के गांवों में किसानों को नरवाई प्रबंधन की वैज्ञानिक जानकारी दी जा रही है।

कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि रबी कटाई के बाद अप्रैल-मई में यह अभियान तेज कर दिया गया है। वर्तमान में मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल, चंबल और विंध्य क्षेत्र के सभी 313 विकासखंडों में 'कृषि चौपाल' आयोजित की जा रही हैं। बड़े स्तर पर नरवाई प्रबंधन पर चर्चा हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा परियोजना और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से लाइव प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।

मंत्री कंषाना ने कहा कि नरवाई जलाने के कई दुष्परिणाम हैं। इसे जलाने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है। लगभग 1 टन नरवाई जलाने से 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फॉस्फोरस, 25 किलो पोटाश व 400 किलो कार्बनिक

पदार्थ जल जाते हैं, जिससे मित्र कीट मर जाते हैं। पर्यावरण व स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। धुएं से जहरीली गैसें बढ़ती हैं, जिससे सांस व आंखों के रोग होते हैं। दृश्यता घटने से सड़क हादसे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर नरवाई जलाना दंडनीय अपराध है और जुर्माने का प्रावधान है।

मंत्री कंषाना ने कहा कि नरवाई नहीं जलाने के फायदे हैं। इसे खेतों में मिलाने से भूमि की सेहत सुधरती है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर से नरवाई खेत में मिलाने पर जैविक कार्बन बढ़ता है, पानी रोकने की क्षमता 30 प्रतिशत बढ़ती है। किसानों को अतिरिक्त आय भी होती है।

महापौर श्रीमती राय ने शिवालय निर्माण हेतु किया भूमिपूजन

भोपाल। महापौर श्रीमती मालती राय ने करूणाधाम आश्रम में शिवालय निर्माण हेतु विधिवत भूमिपूजन किया।

महापौर श्रीमती मालती राय ने शुक्रवार को करूणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुरेश शांडिल्य महाराज के सानिध्य में नेहरू नगर स्थित करूणाधाम आश्रम में भव्य शिवालय निर्माण कार्य हेतु विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन मौजूद थे।

एंकर नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू...फोटोयुक्त मतदाता सूची का हो रहा पुनरीक्षण

पुराने परिसीमन पर ही होंगे निकाय और पंचायत चुनाव!

भोपाल टुडे, भोपाल।

मप्र में 2027 में होने वाले नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। एक जनवरी 2026 को संदर्भ तारीख मानकर यह पुनरीक्षण किया जाएगा। यह इस बात का संकेत है कि राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों के लिए परिसीमन नहीं कराएगा। यानी आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन (वर्ष 2022) पर ही होंगे।

मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति तथा जिला स्तरीय प्रशिक्षण

27 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 15 मई को किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची पर आम नागरिकों के दावे और आपत्तियां 25 मई तक स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त सभी दावों-आपत्तियों का निराकरण 30 मई तक कर दिया जाएगा। अंत में, फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 18 जून को होगा। यह पुनरीक्षण कार्यक्रम मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नए मतदाताओं का नाम जुड़ना, पुराने नाम हटना, नाम, पते, फोटो में सुधार जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

पंचायत चुनाव के कारण प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज: प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जून, 2027 में प्रस्तावित हैं। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में नगरीय निकास और पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि देश में जनगणना के चलते गत 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। अब जनगणना पूरी होने तक नए जिले, तहसील का गठन और किसी तरह का सीमा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में घरों की लिस्टिंग और आवास गणना अप्रैल से सितंबर, के बीच होगी। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना फरवरी, 2027 में की जाएगी।

नए आयोग का गठन ठंडे बस्ते में: राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले साल होने वाले चुनाव से पहले नगरीय निकायों और पंचायतों की सीमाओं का नए सिरे से परिसीमन करने का निर्णय लिया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने जुलाई, 2025 में राज्य शासन को एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में नगरीय निकायों एवं पंचायतों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए नए परिसीमन आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग को उम्मीद थी कि सरकार जल्द आयोग का गठन कर देगी, जिससे प्रशासनिक इकाइयां फ्रीज होने से पूर्व नगरीय निकायों और पंचायतों के परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सरकार को प्रस्ताव भेजने के नौ महीने बीतने के बाद भी परिसीमन आयोग के गठन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक मोनालिशा पाण्डे द्वारा साईं प्रिंटर्स मकान नं. 91 शॉप -3, जिंसी पुलिस चौकी के पीछे जहांगीराबाद भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं 1/2 मीरा कॉम्प्लेक्स, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल से प्रकाशित। संपादकीय कार्यालय 501 इसराणी लॉ चेबर, अरेरा हिल्स, भोपाल। संपादक - पी. पाण्डे, समाचार पत्र में समाचार चयन के लिए पीआरबी एट के तहत जिमेदार। (सभी विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल न्यायालय के अंतर्गत ही मान्य होगा।) **RNI NO. MPHIN**/2015/62492, मोबाइल-8770015502 टेलीफोन नं. 0755-4933451